@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive www.kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

'हमने झारखंड को विकास का नया डेस्टिनेशन बना दिया है'

वर्ष-14, अंक-24 16-31 दिसम्बर, 2019 (पाक्षिक) ₹20

झारखंड विधानसभा चुनाव–2019

सबका विकास भाजपा का ध्येय

गढ़वा (झारखंड) में एक विशाल रैली को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

चेन्नई आगमन पर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते तमिलनाडु भाजपा कार्यकर्तागण और साथ में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व तमिलनाडु प्रभारी श्री मुरलीधर राव

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, अलीपुर, नई दिल्ली में बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई पर 26/11 आतंकी हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्र उनके परिवारजनों के साथ केंद्रीय मंत्रीगण श्री राजनाथ सिंह व श्री नितिन गडकरी

मधुपुर (झारखंड) में एक विशाल रैली को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 भाजपा ने राज्य को शांति और विकास की तरफ अग्रसर किया: नरेन्द्र मोदी

भाजपा की सरकार के कारण झारखंड में सालों से लटकी पानी की योजनाएं फिर से शुरू हुई हैं। अब भाजपा सरकार का संकल्प है कि 2024 तक देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। एक तरफ आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीब...

वैचारिकी

समाज की सर्वांगीण उन्नति हमारा ध्येय 18

श्रद्धांजलि

कमल संदेश संपादकीय बोर्ड के सदस्य सत्यपाल जी का निधन 20

लेख

मेरे अटल जी 22

साक्षात्कार

भाजपा को राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान सुशासन, पारदर्शी और स्थिर सरकार देने का लाभ मिलेगा: ओपी माथुर 32

अन्य

'हमने झारखंड को विकास का नया डेस्टिनेशन बना दिया है' 12

'राज्य में पांच साल भ्रष्टाचारमुक्त और विकासयुक्त सरकार मिली' 14

भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने की मंजूरी 17

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने मालदीव में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया 21

हमारे संविधान में समावेशन की शक्ति है: नरेन्द्र मोदी 24

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून सभी के लिए बराबर है: अमित शाह 26

संसद में दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 पारित 27

और मजबूत हुआ भारत-जापान के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग 28

श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर का ऋण देगा भारत 29

'बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर' 31

तीनों सेनाओं के लिए 22,800 करोड़ रुपये के पूंजीगत सामान की खरीद को मंजूरी 33

जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की 34

08 'भाजपा सरकार ने नक्सलवाद की कमर तोड़ी'

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथी, जो सड़कों पर काम करते हैं, घरों में, दुकानों में काम करते हैं...

10 कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत

कर्नाटक में मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी भाजपा ने 09 दिसंबर, 2019 को उपचुनाव के नतीजों की घोषणा के...

15 कार्टोसैट-3 और 13 व्यावसायिक नैनो उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन ने अपनी 49वें उड़ान (पीएसएलवी-सी47) में कार्टोसेट-3 के साथ अमेरिका के 13 नैनो उपग्रहों...

16 2014 से भारतीय रक्षा उद्योग के साथ 1,96,000 करोड़ रुपये के 180 से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर

रक्षा मंत्रालय ने 2014 से भारतीय रक्षा उद्योग के...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

नरेन्द्र मोदी

जेएमएम-कांग्रेस और भाजपा की प्राथमिकताओं में फर्क साफ है। उनकी प्राथमिकताएं खुद के लिए बड़े-बड़े घर बनाना है, भ्रष्टाचार और अस्थिरता को बढ़ावा देना है। उन्हें गरीबों की परवाह नहीं है। वहीं, हम गरीबों के लिए घर बनाना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करना चाहते हैं।

अमित शाह

मुझे समझ नहीं आता, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, चाहे 370 हो या कैब; कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के बयान हमेशा एक समान कैसे होते हैं।

जगत प्रकाश नड्डा

झामुमो और कांग्रेस के नेता हमेशा समाज को बांटने और तोड़ने की बात करते थे। आज इनको भी मजबूरी में विकास की बात करनी पड़ रही है। इसलिए नहीं कि ये विकास करेंगे, बल्कि इसलिए कि मोदी का जमाना है, बिना विकास के कुछ नहीं होने वाला है।

facebook

ग्रामीण भारत को सड़कों से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 263.72 करोड़ रुपए की 12 सड़कें (लम्बाई 287.225 कि.मी.) और 11 पुल (लम्बाई 372.55 मी.) स्वीकृत।

— नरेन्द्र सिंह तोमर

वर्षों से सताये हुए उत्पीड़न और भेदभाव के साथ धार्मिक आजादी से वंचित लोगों के लिए भारत ने अपनी नागरिकता के द्वार खोल दिए हैं। एक समय में भारत का हिस्सा रहे इन देशों के लोगों की सहायता करना हमारा दायित्व है और हमने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

— पीयूष गोयल

वर्तमान (कांग्रेस) सरकार का 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा केवल एक छलावा साबित हुआ है। जब तक प्रदेश सरकार वादे के अनुसार धान नहीं खरीदती तब तक कृषक भाइयों के हित में हम प्रदर्शन जारी रखेंगे।

— डॉ. रमन सिंह

'कमल संदेश' परिवार

की ओर से

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी

को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है!

शत शत नमन!

जन्मदिन : 25 दिसंबर

दृढ़ इच्छाशक्ति की धनी मोदी सरकार

देश के अनेक चिरलंबित समस्याओं का अत्यधिक कुशलता से समाधान करने के लिए मोदी सरकार को आने वाले समय में जाना जाएगा। ये इस प्रकार की समस्यायें थीं जिनका समाधान असंभव माना जाता था तथा राष्ट्र की प्रगति में बाधा बने हुए थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति, अटूट प्रतिबद्धता, पूर्ण समर्पण, दूरदर्शिता तथा हृदय में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की आवश्यकता थी। ये समस्यायें वोट–बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण खड़ी की गई कई प्रकार की बाधाओं से और भी अधिक जटिल प्रतीत होती थीं। इन समस्याओं से समाज में अविश्वास एवं संदेह का वातावरण बना हुआ था, जिस कारण लोग निराशा और आशंकाओं से भरा जीवन जीने के लिए बाध्य थे। ऐसा लगता था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी समस्याओं का निराकरण कर पाने में असमर्थ है तथा इतने प्रकार के अंर्तद्वंद्व एवं जटिलताओं को अपने में समेटे हुए हैं कि किसी भी क्षण कुव्यवस्था एवं अराजकता देश में घर कर सकती थी। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में जिस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान निकाला गया है, उससे यह कहने में अब कोई संशय नहीं है कि देश प्रगति एवं विकास के पथ पर अब बढ़ चला है।

अंत्योदय के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याणार्थ मोदी सरकार ने अनेक अभिनव कार्यक्रमों का शुभारंभ तो किया ही, साथ ही अनेक ऐसे राजनैतिक निर्णय लिये जिससे संपूर्ण देश में आशा एवं विश्वास के वातावरण का निर्माण हुआ है। राजनैतिक प्रतिबद्धता एवं दृढ़ इच्छाशक्ति का एक अद्भुत उदाहरण जिस प्रकार धारा 370 का संशोधन कर क्रियान्वित किया, उसमें देखा जा सकता है। यह माना जाता था कि कश्मीर समस्या का समाधान असंभव है तथा कश्मीर की जनता को शेष भारत की मुख्यधारा में लाना दुष्कर है। परंतु इस निर्णय से यह प्रमाणित हो गया कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इसी प्रकार से 'तीन तलाक' के विषय पर तुष्टिकरण की राजनीति के अनैतिक दबाव से कांग्रेस की सरकारें निर्णय को टालती रही, परंतु मोदी सरकार के द्वारा न्यायालय में सुविचारित एवं स्पष्ट मत रखने के बाद मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला एवं करोड़ों मुस्लिम महिलाएं इस अमानवीय कुप्रथा से आजाद हो गईं। यहां तक कि श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे न्यायिक प्रक्रिया पर भी निरंतर अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास हुए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्पष्ट एवं सर्वसम्मत निर्णय देकर समाज में शांति एवं सद्भाव का वातावरण निर्माण किया है। एनआरसी का विषय जो लंबे समय से लंबित था उस पर भाजपा सरकार ने पूरी गंभीरता दिखाई है जो कि घुसपैठ समस्या का विशेषकर असम तथा पूरे देश में समाधान प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्पित है। कई महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से मोदी सरकार ने देश में 'वीआईपी संस्कृति' पर भी कुठाराघात किये हैं। इन ऐतिहासिक निर्णयों से देश का राजनैतिक चित्र तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने वाला है तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत देने वाला है। कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों ने जिस प्रकार से इस विधेयक का विरोध करने का प्रयास किया है, उससे इन दलों की 'वोट बैंक' एवं तुष्टीकरण की राजनीति पुनः बेनकाब हुई है।

इस संसद सत्र में भी मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं। संसद में एसपीजी कानून में संशोधन कर यह प्रमाणित किया गया है कि देश के कानून किसी एक परिवार विशेष के लिए न होकर लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उपयोग किसी के लिए 'स्टेटस सिंबल' के रूप में नहीं हो सकता, बल्कि आवश्यकताओं के अनुसार ही तय हो सकता है। इसी प्रकार से नागरिकता संशोधन कानून 2019 ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने वाला है तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत देने वाला है। कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों ने जिस प्रकार से इस विधेयक का विरोध करने का प्रयास किया है, उससे इन दलों की 'वोट बैंक' एवं तुष्टीकरण की राजनीति पुनः बेनकाब हुई है। कांग्रेस भारत विभाजन की अपनी ऐतिहासिक गलतियों के लिए प्रायश्चित करने से एक बार पुनः चूक गई है। आने वाले समय में भी देश की जनता कांग्रेस को और भी अधिक कड़े पाठ पढ़ायेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का इन चिरलंबित समस्याओं का दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति के लिए सारा देश अभिनंदन कर रहा है। साथ ही, जिस प्रकार से देश के गृहमंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 'नए भारत' को जमीन पर उतारने के लिए अपने राजनैतिक कौशल का प्रदर्शन किया है, उसकी देश के कोने–कोने में भूरि–भूरि प्रशंसा हो रही है। अब समय आ गया है कि प्रतिबद्धता, समर्पण एवं कड़ी मेहनत से देश को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोटि–कोटि जन कृतसंकल्पित हों। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

भाजपा ने राज्य को शांति और विकास

भाजपा की सरकार के कारण झारखंड में सालों से लटकी पानी की योजनाएं फिर से शुरू हुई हैं। अब भाजपा सरकार का संकल्प है कि 2024 तक देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। एक तरफ आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीब से गरीब परिवार को आज 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं, दूसरी तरफ देशभर के 50 करोड़ से अधिक पशुओं के मुफ्त टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ये बातें झारखंड के बरही में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने 9 दिसंबर को बरही और बोकारो में दो विशाल रैलियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार ईमानदारी से काम करती है। देश के आदिवासियों और पिछड़ों की जिंदगी को और बेहतर करने के लिए यह सरकार दिन-रात मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा, "2014 से पहले 8-9 साल में आदिवासियों को जमीन के सिर्फ 19 हजार पट्टे ही मिल पाए थे, जबकि भाजपा ने बीते 5 वर्ष में 60 हजार से अधिक जनजातीय परिवारों को जमीन के पट्टे दिए हैं।"

श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर है और सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम है। यही कारण है कि बीते 5 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों की गलत नीतियों ने झारखंड को नक्सलवाद की तरफ धकेला जबकि भाजपा ने उसे शांति और विकास की तरफ अग्रसर किया है। उन्होंने कहा, "नक्सली हिंसा से झारखंड अब पूरी तरह मुक्त होने की ओर बढ़ चला है। 2014 से पहले जहां गिने-चुने नक्सली आत्मसमर्पण करते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार झारखंड में एयर और वाटर कनेक्टिविटी पर पूरा बल दे रही है। बनारस से हल्दिया के बीच बन रहे देश के पहले इनलैंड वाटरवे का बहुत बड़ा लाभ झारखंड के उद्योग और व्यापार को हो रहा है। श्री मोदी ने कहा, "भाजपा सरकार झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को 21वीं सदी का बनाने के लिए काम कर रही है। यहां गैस और सोलर पावर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। भाजपा सरकार के प्रयासों से झारखंड आज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का अहम लाभार्थी है।"

उन्होंने कहा कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों ने देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है लेकिन पहले यहां स्थानीय लोगों के हितों का कभी ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा, "भाजपा की सरकार ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का गठन किया। झारखंड को इसके तहत करीब 5 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। भाजपा की सरकार इस राशि से राज्य में पानी की पाइपलाइन बिछाने और स्कूल-अस्पताल बनवाने के

स की तरफ अग्रसर किया: नरेन्द्र मोदी

साथ दूसरी सुविधाओं का निर्माण कर रही है।"

श्री मोदी ने कहा कि झारखंड में 2014 से पहले ग्राम प्रधान, पंचायत सेवक और बिचौलियों के गठजोड़ से गरीबों के ज्यादातर घर केवल कागजों पर ही बनते थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क को तोड़ा है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में 10 लाख घर बनाए हैं, जबकि 8 लाख घरों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।"

श्री मोदी ने कहा कि 5 साल पहले छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आया है। बैंक के दरवाजे अब आम जनता के लिए खुल गए हैं। उन्होंने कहा, "सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत करीब 20 करोड़ ऋण दिए जा चुके हैं। इनमें 10 लाख करोड़ रुपये के करीब स्वरोजगार में लगे हैं। पिछले कुछ समय में ही छोटे उद्योगों को सरकारी बैंकों से 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण मिल चुका है। इससे इन उद्योगों में नए रोजगार का निर्माण तय है।"

उन्होंने कहा कि देश के 100 से अधिक जिले ऐसे हैं, जहां बिजली, पानी, घर, गैस, टीकाकरण जैसी अनेक चुनौतियां हैं। इन जिलों में गरीब माताओं और बच्चों की मृत्यु सबसे ज्यादा होती है। इन 100 जिलों में झारखंड के 20 जिले शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों की सरकार ने इन जिलों के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। श्री मोदी ने कहा, "हम इन जिलों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। बेहतरीन अफसर तैनात किए गए हैं। छोटी-छोटी दिक्कतों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड की भाजपा सरकार की मेहनत के कारण हजारीबाग, चतरा और साहिबगंज जैसे जिले टॉप प्रदर्शन करने वालों में हैं।"

श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक में आए उपचुनाव के नतीजे कोई सामान्य नतीजे नहीं हैं। इसमें यह संदेश छुपा है कि कांग्रेस और उसके साथियों के गठबंधन से झारखंड को भी सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस कभी भी गठबंधन के भरोसे पर खरी नहीं उतरी है। ये अपने मतलब के लिए गठबंधन और जनादेश का उपयोग करती है और फिर अपने हित के लिए अपने सहयोगियों को कठपुतली की तरह उपयोग करती है।"

उन्होंने कहा कि 19-25 साल का कालखंड भविष्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेटे-बेटी के 19 वर्ष होने पर जैसे मां-बाप उसके बेहतर भविष्य के लिए विचार विमर्श करते हैं, उसी तरह, 19 साल के झारखंड को लेकर भी सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "यह चुनाव आपके लिए फैसला लेने का मौका है कि आप आने वाले समय में कैसा झारखंड चाहते हैं।" ■

'भाजपा सरकार ने नक्सलवाद की कमर तोड़ी'

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथी, जो सड़कों पर काम करते हैं, घरों में, दुकानों में काम करते हैं या रिक्शा-ठेला चलाते हैं, उनकी चिंता पहली बार भाजपा सरकार ने की है। श्रमयोगी मानधन योजना से ऐसे साथियों को 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा दी गई है। देश के किसानों, खेत-मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिए 60 साल की उम्र के बाद निश्चित पेंशन योजना की शुरुआत का गौरव भी झारखंड को मिला है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ये बातें झारखंड के खूंटी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने 3 दिसंबर को खूंटी और जमशेदपुर में दो विशाल रैलियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि आज झारखंड के हर व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की किसी न किसी योजना का सीधा लाभ पहुंच रहा है। वर्ग, जाति और पंथ के आधार पर भेदभाव किए बिना, हर झारखंडवासी के विकास के लिए समान भावना से हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारा मूलमंत्र है।"

उन्होंने कहा कि झारखंड में पहले चरण के मतदान से तीन बातें स्पष्ट हुई हैं। पहली- लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में झारखंड के लोगों की आस्था अभूतपूर्व है। दूसरी- भाजपा सरकार ने जिस प्रकार नक्सलवाद की कमर तोड़ी है, उससे यहां डर का माहौल कम हुआ है और विकास का माहौल बना है। तीसरी- झारखंड के लोगों में भाजपा सरकार के प्रति एक विश्वास की भावना है।

श्री मोदी ने कहा कि हमने देश में शांति, एकता, सद्भाव के लिए समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र और झारखंड की भाजपा सरकार ने गांव और जनजातीय अंचलों में महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा, "झारखंड देश के उन राज्यों में है, जहां की बहनों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से तो मिला ही है, डबल लाभ भी मिला है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत बाकी देश में एक मुफ्त सिलेंडर मिला है, वहीं झारखंड में दो सिलेंडर दिए गए हैं।"

श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार ने ही पहली बार आदिवासी क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की व्यवस्था की, जिसके तहत अब यहां से निकलने वाले खनिज का एक हिस्सा यहीं के विकास में लगता है। झारखंड को इस फंड के तहत पांच हजार करोड़ रुपये मिले है। इस फंड से ही बच्चों के लिए स्कूल और अस्पतालों के निर्माण में सहायता मिल रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अपनी सरकार के पांच साल में झारखंड के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दो हजार करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जबकि भाजपा सरकार के दौरान बीते पांच वर्ष में इसका पांच गुना यानी 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम आवंटित की गई है। 2014 से पहले के 5 वर्ष में जहां झारखंड में 300 किलोमीटर से कम की रेल लाइनें चालू हुईं, वहीं केंद्र में भाजपा शासन के दौरान करीब 700 किलोमीटर लाइनें खोली गईं। उन्होंने कहा, "आजादी के साढ़े छह दशक तक झारखंड में सिर्फ तीन ही मेडिकल कॉलेज थे। बीते पांच साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या सात हो चुकी है। इसके साथ ही जो पुराने जिला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनके आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का काम भी आने वाले समय में हम तेज करने वाले हैं।"

जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज भाजपा ने केंद्र सरकार को दिल्ली से बाहर निकालकर देश के कोने-कोने तक पहुंचाया है। दशकों से चली आ रही इस व्यवस्था में परिवर्तन का बहुत बड़ा लाभ झारखंड को मिला है। आज झारखंड भारत के इतिहास की कुछ क्रांतिकारी योजनाओं की गंगोत्री और उद्गम स्थली बनी है।

उन्होंने कहा कि 2022 तक देश के हर आदिवासी बहुल ब्लॉक तक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने की शुरुआत भी झारखंड से ही हुई है। इसके अलावा झारखंड की धरती से ही ग्रामोदय से भारत उदय का सफल अभियान भी शुरू किया था और इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम भी यहीं किया गया। आयुष्मान योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसकी शुरुआत का गौरव झारखंड के खाते में है।

श्री मोदी ने कहा कि राम जन्मभूमि विवाद को कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारों ने लगातार लटकाए रखा, उसका भी अब शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो गया। उन्होंने कहा, "भगवान राम अयोध्या से जब निकले थे, तब तो राजकुमार राम थे और जब 14 साल के वनवास के बाद वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 14 साल भगवान राम ने आदिवासियों के बीच बिताए थे। ये संस्कार हैं आदिवासी भाई-बहनों के।"

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से हिंदुस्तान के हर कोने में जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 की चर्चा चल रही थी। संविधान में 370 को अस्थायी लिखा था, लेकिन एक टोली उसे स्थायी बनाने में जुटी थी, कोई उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं था। अब इसका भी समाधान हो गया है। श्री मोदी ने कहा, "देश की जनता ने मोदी को कठोर निर्णय लेने के लिए भेजा है। मैं राजनीति का हिसाब किताब नहीं करता हूं, मैं सिर्फ देशनीति को देखता हूं। इसलिए दशकों से लटका 370 खत्म हो सका।"

खूंटी और जमशेदपुर की रैलियों में भारी संख्या में पहुंचे लोगों से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रिकॉर्ड मतदान कर झारखंड में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। ■

कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत

जनादेश के खिलाफ जानेवाले कांग्रेस–जद(एस) को जनता ने किया दंडित

कर्नाटक में मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी भाजपा ने 09 दिसंबर, 2019 को उपचुनाव के नतीजों की घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा में अपना बहुमत स्थापित किया। इस उपचुनाव में भाजपा ने 15 में से 12 सीटें जीतीं, जिसके लिए 05 दिसंबर, 2019 को मतदान हुआ था।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन में दरार आने के बाद इन विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई 17 विधानसभा सीटों में से 15 सीटों पर उपचुनाव को आयोजित किया गया था। जिन 15 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 12 सीटों पर पहले कांग्रेस और शेष तीन पर जेडीएस का कब्जा था।

उपचुनाव के नतीजे सभी राज्यों के लिए एक संदेश है: प्रधानमंत्री मोदी

जीत के बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कर्नाटक उपचुनाव परिणाम सभी राज्यों के लिए एक संदेश है कि लोग उन लोगों को दंडित करेंगे जो लोकप्रिय जनादेश के खिलाफ जाएगा। झारखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कहा कि भाजपा का देश के दक्षिणी हिस्से में सीमित प्रभाव है, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से लोगों ने दंडित किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कांग्रेस पर कर्नाटक में लोगों के जनादेश को पिछले दरवाजे से चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कर्नाटक में जनादेश को उलट दिया और यहां की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। इसलिए यह दल अब धूल फांक रहे हैं।

"कर्नाटक के लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि कांग्रेस या जेडीएस उन्हें पुनः धोखा नहीं दे पाएं और यह संदेश सभी राज्यों के लिए है कि लोकप्रिय जनादेश के खिलाफ जाने वालों को जनता दंडित करेगी।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। उपचुनाव के नतीजों से पता चलता है कि मतदाताओं ने यह सुनिश्चित किया है कि कांग्रेस और जद (एस) उनकों फिर से धोखा नहीं दे।"

उन्होंने आगे कहा कि "झारखंड के लोगों को भी कर्नाटक से सीखना चाहिए कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में झारखंड कर्नाटक जैसी स्थिति का सामना करेगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी राज्य में उपचुनावों में भाजपा की शानदार जीत के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदिुरप्पा और कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

कर्नाटक भाजपा ने जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में कहा गया, "उपचुनावों में भाजपा के लिए आज की शानदार जीत येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में भाजपा की "विकास राजनीति" की जीत है।"

कांग्रेस और जनता दल (एस) के "एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स" को अस्वीकार करके मतदाताओं ने भाजपा में अपना विश्वास दोहराया है।"

केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक उपचुनाव के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक ही रहे, "यह नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही है। कर्नाटक के लोगों को एक स्थिर सरकार की जरूरत है।"

उन्होंने कहा कि सुशासन और विकास दोनों ही मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार बेहद सर्तक रही। सुशासन और विकास ऐसे मुद्दे है जो जेडीएस-कांग्रेस की गठबंधन सरकार के दौरान गायब रहे।

इस साल जुलाई में एक नाटकीय गतिरोध के बाद पद छोड़ने वाले विधायकों को तत्कालीन अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने अयोग्य घोषित कर दिया था और 2023 तक चुनावों पर रोक लगा दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता का समर्थन किया लेकिन सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी। इस बार दोनों पूर्व सहयोगी कांग्रेस और जेडीएस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा। इन दोनों दलों के बीच गठबंधन टूटने के बाद दोनों से ही इनके संबंध कभी मधुर नहीं रहे।

इस जीत के बाद अब मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा कर्नाटक में एक स्थिर सरकार दे सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार में बहुमत बनाए रखने के लिए आवश्यक छह सीटों के आंकड़े को भाजपा ने हासिल कर लिया है।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि बिना किसी समस्या के भाजपा राज्य में "जनसमर्थित और स्थिर सरकार" दे सकती है।

कर्नाटक में विधानसभा उपचुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नलिन कटील ने कहा, "कांग्रेस और जेडीएस को जनता की अदालत ने अयोग्य ठहराया है।"

श्री कटील ने कहा कि भाजपा ने पहली बार मंड्या जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे केआर पेट और चिक्काबल्लपुरा जहां हमारी उपस्थिति कमजोर थी। मांड्या जद (एस) का गढ़ रहा था, लेकिन आज भाजपा मांड्या जिले में केआर पेट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि येदियुरप्पा सरकार अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करेगी और राज्य को प्रगति की ओर ले जाएगी। ■

'यह जीत भाजपा की नीतियों में जनता के विश्वास का परिणाम'

कर्नाटक उपचुनावों में भाजपा की शानदार जीत पर बोलते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कर्नाटक विधान सभा उप-चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं भाजपा की नीतियों में जनता के विश्वास का परिणाम है। कर्नाटक की जनता ने भाजपा की सरकार में अपने विश्वास को और मज़बूती के साथ परिलक्षित किया है। इस जीत के लिए मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी. एस. येदियुरप्पा और प्रदेश अध्यक्ष श्री नलिन कटील को बधाई देता हूं और भाजपा कार्यकर्ताओं एवं प्रदेश की जनता हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश देकर प्रदेश की जनता ने स्वार्थी और भ्रष्टाचारियों को सिरे से खारिज कर दिया है। राज्य की जनता ने विधानसभा चुनावों में भी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को ही दिया था और आज उप-चुनावों में कर्नाटक की जनता ने उस पर पक्की मोहर लगा दी है।

उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक विधान सभा उप-चुनाव परिणाम कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों एवं अवसरवादी राजनीति पर राज्य की जनता का कड़ा प्रहार है। कर्नाटक की जनता ने जनादेश का अपमान करने वाली और जनादेश के साथ विश्वासघात करने वाली कांग्रेस को इस परिणाम से करारा सबक सिखाया है। यह इस बात की भी परिचायक है कि जनता का भाजपा में विश्वास कितना दृढ़ है। कर्नाटक की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की देश भर में चल रही विकास यात्रा के साथ है और वे विकास की दौड़ में पीछे नहीं छूटना चाहते।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मैं भाजपा में अपना विश्वास रखने के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं सीएम येदियुरप्पा जी, राज्य में मंत्रियों की टीम और कर्नाटक प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं को पूरी लगन के साथ लोगों की सेवा करने के लिए बधाई देता हूं। कर्नाटक ने विकास के लिए वोट दिया है और अवसरवाद को दंडित किया है।

अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

कर्नाटक उपचुनावों में भाजपा की शानदार जीत पर येदियुरप्पा जी, श्री नलिन कटील और हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई। मैं कर्नाटक के लोगों को भाजपा में अटूट विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार कर्नाटक में पीएम नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बदलना को जारी रखेगी।

जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों पर विश्वास कर कर्नाटक उपचुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत को सुनिश्चित किया है। राज्य के लोगों ने कर्नाटक की भाजपा सरकार में अपने विश्वास को और अधिक मजबूती से दोहराया है।

इस जीत के लिए मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री नलिन कटील जी को बधाई देता हूं और भाजपा कार्यकर्ताओं और राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं।

बी.एस. येदियुरप्पा, मुख्यमंत्री, कर्नाटक

मुझे खुशी है कि लोगों ने कर्नाटक उपचुनाव में बहुत अच्छा फैसला दिया है। अब, बिना किसी समस्या के हम एक जनसमर्थित और एक स्थिर सरकार दे सकते हैं।

हमने झारखंड को विकास का नया डेस्टिनेशन बना दिया है : अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने झारखंड के चतरा में एक चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस और झामुमो यहां साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन झामुमो नेता ने कभी कांग्रेस से यह नहीं पूछा कि उन्होंने झारखंड की स्थापना के लिए क्या किया। 60 साल के शासन में आखिर कांग्रेस ने झारखंड को क्या दिया। श्री शाह ने कहा कि अब हमारी सीमा में आलिया-मालिया-जमालिया नहीं घुसता है। अब मौनी बाबा का जमाना नहीं, यह मोदी जी की सरकार है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म कर हमने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कांग्रेस की तमाम अड़चनों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम मंदिर की सुनवाई आगे बढ़ा दें। कांग्रेस ने अयोध्या मसले को हमेशा लटकाकर रखा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दुनिया का सबसे भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा। भगवान श्रीराम की कृपा से यहां आसमान छूने वाला मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होगा।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस की यूपीए शासन से छह गुना पैसा झारखंड के विकास के लिए दिया। रेलवे में भी झारखंड में कई प्रोजेक्ट शुरू हुए। युवाओं से पूछा- आप बताइए कि देश की सुरक्षा चाहते हैं कि कांग्रेस शासन में मौनी बाबा की चुप्पी से आलिया-मालिया-जमालिया भारत में रोज घुस आते थे। हमारे जवानों का सिर काटकर ले जाते थे। उरी पुलवामा के हमले के बाद हमारे एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का चिथड़ा उड़ा दिया। अब भारत पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एम्स, मेडिकल कॉलेज से लेकर कल-कारखाने तक आज झारखंड की उन्नति की कहानी बयां कर रही है। मोदीजी ने झारखंड की पूरी चिंता की है। अब हम पाइपलाइन से हर गरीब के घर में पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस और हेमंत सोरेन का स्वार्थी गठबंधन को देखिए। कांग्रेस ने झारखंड बनने का विरोध किया था, फिर भी हेमंत उनकी गोद में बैठ गए।

श्री शाह ने कहा कि उज्ज्वला के तहत हमने गरीबों के घर में गैस का चूल्हा और सिलिंडर दिया। हमने उनके घर को धुएं से मुक्त कर दिया। हमने झारखंड को विकास का नया डेस्टिनेशन बना दिया है। एक रुपये में माता-बहनों की रजिस्ट्री झारखंड ने शुरू कर इतिहास बनाया है। इस राज्य का जीडीपी नई ऊंचाइयां छू रहा है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप एक बार फिर भाजपा सरकार बनाइए। सरकार पहला फैसला ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने का लेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा की रघुवर सरकार ने घर-घर बिजली पहुंचा दी। कांग्रेस के 70 साल के शासन में गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची। मोदी सरकार ने ढाई करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई है। अब हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा मिली। देशभर में हमने 10 करोड़ शौचालय बनाए। पहले कोई बीमार

पड़ता था तो एंबुलेंस नहीं मिलता था, अब 108 पर फोन करते ही तुरंत एंबुलेंस आ जाता है। आयुष्मान भारत से अब आपकी बीमारी का पांच लाख रुपये तक का खर्च सरकार उठाती है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 515 करोड़ की लागत से हमने सिर्फ सड़कें बनाई हैं। आप बताएं कि पहले और अब की सड़कों में आपको अंतर दिखता है कि नहीं। उत्तर कोयल नहर का निर्माण हमने किया। मंगल डैम को मोदी सरकार ने पूरा किया। गढ़वा से चिनियां, मझिआंव को हमने जोड़ा।

उन्होंने कहा कि भाई रघुवर दास का अभिनंदन जिन्होंने झारखंड से नक्सलवाद को जमीन के दस फीट नीचे दफन कर दिया। मैं यहां नक्सलियों को चेतावनी देने आया हूं कि जितनी खैर मनानी है मना लो हम फिर से यहां सरकार बना रहे हैं। विकास बुलेट से नहीं बैलेट से होता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि सत्ता के लिए भाई हेमंत कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। मैं हेमंत को पूछना चाहता हूं कि जब झारखंड के युवा अलग राज्य के लिए बलिदान दे रहे थे, तब कांग्रेस क्या कर रही थी। मुझे बताएं भाइयों बहनों क्या हेमंत का यह कदम उचित है क्या। झारखंड तब मिला जब अटलजी सत्ता में आए। झारखंड को अटलजी ने बनाया, मोदीजी और रघुवर दास ने संवारने का काम किया है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं। जब भी वोट देने जाएं, अस्थिर सरकारों की ओर न देखें। कभी कोई निर्दलीय मुख्यमंत्री बना, कभी लंगड़ी सरकार बनी, सबने मिलकर झारखंड को लूट लिया। आपने पांच साल के लिए भाजपा सरकार चुनी तो हमने दिन-रात काम करके झारखंड के विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया है।

उन्होंने कहा कि कई सालों से देश की जनता चाहती थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने। जब आप सब चाहते थे, तो अब तक मंदिर का रास्ता क्यों प्रशस्त नहीं होता था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोर्ट में केस न चले इसमें रोड़े अटकाती थी। अनुच्छेद 370 और 35ए को कांग्रेस ने वोटबैंक की राजनीति के लिए संभालकर रखा था। मोदी जी को आपने 300 से ज्यादा सीटें जिताईं, तो उन्होंने 370 और 35ए को उखाड़कर फेंक दिया। 370 और 35ए को हटाकर मोदी जी ने देश से आतंकवाद के खात्मे की शुरुआत कर दी है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो वाले जाति की बात करेंगे, जात-पात की बात के आधार पर वोट मांगने का काम करेंगे। हमने कोई जाति नहीं देखी, मोदी जी ने एक ही जाति देखी है वो है गरीब। जो गरीब है उसके घर में सीधा फायदा पहुंचे इसका प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। दलितों व आदिवासियों का आरक्षण कम किए बिना ओबीसी समाज को अधिक से अधिक आरक्षण देने का काम, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। झारखंड में 38 लाख गरीब लोगों के घर बिजली पहुंचाने का काम भाजपा ने किया। पिछले 60 साल में झारखंड के सिर्फ 12 प्रतिशत घरों में पानी पहुंचा था, पिछले पांच साल में ये आंकड़ा 35 प्रतिशत हो गया है। सिर्फ चतरा विधानसभा में करीब 73,178 शौचालय बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया, आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,91,271 लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया, इनका 5 लाख रुपये तक का बीमारी का खर्चा भाजपा की सरकार उठाने वाली है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस की सरकार चली लेकिन उन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक सम्मान नहीं दिया। 2014 में नरेन्द्र मोदी सरकार बनी और हमारी सरकार ने 5 साल के अंदर ही ओबीसी समाज को संवैधानिक सम्मान देने का काम किया। मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। झारखण्ड में हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि दोबारा आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। हम सबसे पहला काम एक कमेटी बनाकर ओबीसी समाज को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिले, इस दिशा में करेंगे।

भगवान बिरसा मुंडा ने ही देश में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं भगवान बिरसा मुंडा को याद करके उन सैकड़ों आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण दे दिए। जब-जब कांग्रेस की सरकार रही, तब झारखण्ड की स्थापना नहीं हो सकी। जबकि कई युवा शहीद हुए, कई लोगों ने अपना जीवन लगा दिया था। भाजपा की पांच साल की सरकार को याद कीजिए। पांच साल में हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी झारखण्ड के अंदर उद्योग लाए, रोड का जाल बिछाया। आज डंके की चोट पर रात को 12 बजे भी बारात लेकर जाइए, किसी नक्सली की हिम्मत नहीं है कि कुछ गड़बड़ कर सके। ये नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। आप बताइए कि कमल फूल की सरकार आने से पहले शाम को बारात ले जा सकते थे क्या? क्या शाम को बिटिया की शादी करा सकते थे क्या?

श्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का साठ साल शासन रहा लेकिन गरीबों के घर में गैस का चूल्हा नहीं आया। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो उसने यह दर्द महसूस किया। मोदीजी ने आपकी चिंता की और माताओं और बहनों को उज्ज्वला का साथ मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुकन्या योजना के तहत बेटियों की चिंता की है। घर-घर बिजली पहुंचाने से लेकर सखी मंडल तक का ख्याल हम रख रहे हैं। ■

राज्य में पांच साल भ्रष्टाचारमुक्त और विकासयुक्त सरकार मिली: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पांच साल पहले यहां कोई सरकार स्थिर नहीं थी, भ्रष्टाचारयुक्त सरकार थी। मुख्यमंत्री, मंत्री जेल जा रहे थे, दो-दो साल के लिए सरकारें बन रहीं थी। आपने रघुवर दास जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई और पांच साल भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त स्थिर सरकार आपको मिली। देश बदल गया है। मोदीजी के नेतृत्व वाली सरकार में कोई भारत के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। झारखण्ड में नक्सलवाद था, शाम को घूम नहीं सकते थे। आज सरेआम घूम रहे हैं। एक बार भाजपा को और मौका दो, नक्सलवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे।

श्री नड्डा मांडर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री देव कुमार धान के पक्ष में 4 दिसंबर को चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मजबूत वोट से मजबूत नेतृत्व मिलता है। झारखंड के लोगों ने इस लोकसभा चुनाव में 14 में से 11 सीटें भाजपा को और एक हमारे सहयोगी को जिताई, तो नरेन्द्र मोदी जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। चाहे आजादी दिलाने की बात हो या भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात हो, हमारे आदिवासी भाइयों ने हमेशा देशहित में काम किया है। आदिवासी भाई कहने का मेरा मतबल होता है, सरलता, सबको साथ लेने की ताकत, सौम्यता, सामूहिकता और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाला।

श्री नड्डा ने कहा कि सरकार केवल इसलिए नहीं कि हमें विधायक या मुख्यमंत्री बनना है। भाजपा सरकार इसलिए कि आपकी सेवा करके झारखण्ड को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। 70 साल से अनुच्छेद 370 नासूर था जिसको मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया है। 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर शांति से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद की घटनाएं भी घटी हैं। 2014 में आपने मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। देश में राजनीति की संस्कृति बदल गई है। अब सब कुछ नहीं चलेगा, वही चलेगा जो सही होगा, जो देशहित में होगा।

श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस वोटबैंक की राजनीति करती है। हमारा देश अगर बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा को बंद कर सकता है, तो मुस्लिम महिलाओं पर तीन तलाक की तलवार क्यों लटकी रहे? नरेन्द्र मोदी जी ने कानून बनाकर तीन तलाक को खत्म कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगा रहे थे कि राम जन्मभूमि का फैसला मत करो, इसको टालो, इसका फैसला नहीं आना चाहिए। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि यह फैसला लंबे समय से लटका हुआ है, इसका निर्णय शीघ्र होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से यह फैसला हुआ और रामलला के मंदिर का मार्ग प्रशस्त होने का पूरे देश ने स्वागत किया। जो मसले लटके हुए थे, उनके समाधान की ताकत दिल्ली की पूर्व की सरकारों में नहीं थी। मोदीजी के नेतृत्व में वो सारे रूके हुए फैसले पूरे के पूरे और समाज और देश के हित में किए गए हैं। जो भ्रष्टाचारी नेता दनदनाते थे, जो भ्रष्टाचारी नेता लोगों के हक-हुकूक को मारते थे। आज वो या तो जेल में हैं या बेल पर हैं और जेल के लिए तैयार हो रहे हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि जिन्होंने वन संपदा पर भ्रष्टाचार करके आदिवासियों की जमीन हड़पी, उन दलों का महामिलावटी जमावड़ा हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस है, जिसने झारखण्ड बनने का विरोध किया था, नौजवानों पर गोलियां चलाई थीं और दूसरी झामुमो, आज ये दोनों कुर्सी के लिए मिल गए हैं। ऐसे महामिलावटी घालमेल को सत्ता से दूर रखिए। बोलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है अब स्वीकार। भाजपा सेवा के आधार पर आपसे वोट मांगती है। ■

कार्टोसैट-3 और 13 व्यावसायिक नैनो उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

इसरो ने एक बार फिर से देश को गौरवान्वित किया है: नरेन्द्र मोदी

भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन ने अपनी 49वें उड़ान (पीएसएलवी-सी47) में कार्टोसेट-3 के साथ अमेरिका के 13 नैनो उपग्रहों का 27 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया।

पीएसएलवी-सी47 ने दूसरे प्रक्षेपण पैड से सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर उड़ान भरी। इसके 17 मिनट 38 सेकेंड के बाद कार्टोसेट-3 सूर्य की एक 509 किलोमीटर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। इसके बाद 13 नैनो उपग्रह भी अपनी निर्धारित कक्षाओं में छोड़े गए। पीएसएलवी-सी47 से अलग होने के बाद कार्टोसेट-3 के सौर श्रेणी स्वतः स्थापित हो गए और बेंगलुरू में स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने उपग्रह का नियंत्रण संभाल लिया। आने वाले दिनों में यह उपग्रह अपने अंतिम संचालन स्थिति में लाया जायेगा।

इसरो के अध्यक्ष डॉ. के सिवन ने कहा कि इसरो द्वारा निर्मित कार्टोसेट-3 बहुत जटिल और पृथ्वी पर नज़र रखने वाला उन्नत उपग्रह है। उन्होंने बताया कि यह तीसरी पीढ़ी का सर्वाधिक स्पष्ट तस्वीर लेने वाला उपग्रह है।

कार्टोसेट-3 का जीवनकाल पांच साल का है। यह व्यापक पैमाने पर शहरी योजना, ग्रामीण संसाधन और आधारभूत ढांचे का विकास, तटीय भूमि उपयोग आदि की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। इसरो के अध्यक्ष डॉ. के सिवन ने मिशन से जुड़े प्रक्षेपण वाहन और उपग्रह टीम को बधाई दी। उन्होंने भारतीय उद्योग की मदद की भी सराहना की।

पीएसएलवी सी-47 एक्सएल आकृति में पीएसएलवी की 21वीं उड़ान है। यह श्रीहरिकोटा में एसडीएससी एसएचएआर से 74वां प्रक्षेपण वाहन मिशन और कार्टोसैट श्रृंखला का नौंवा उपग्रह था। श्री हरिकोटा में लगभग पांच हजार लोगों ने उपग्रहों का प्रक्षेपण होते देखा है।

प्रधानमंत्री ने पीएसएलवी–सी–47 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो की टीम को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी कार्टोसैट-3 उपग्रह और अमरीका के एक दर्जन से अधिक नैनो उपग्रहों सहित पीएसएलवी-सी-47 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं स्वदेशी कार्टोसैट-3 उपग्रह और अमरीका के एक दर्जन से अधिक नैनो उपग्रहों सहित पीएसएलवी-सी-47 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्नत कार्टोसैट-3 से हमारी हाई रिजोल्यूशन क्षमता बढ़ेगी। इसरो ने एक बार फिर से देश को गौरवान्वित किया है।' ■

नवंबर में जीएसटी वसूली छह प्रतिशत वृद्धि के साथ 1.03 लाख करोड़ रुपये

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह नवंबर में पुनः एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार किया। नवंबर में जीएसटी संग्रह एक साल पहले इसी माह की तुलना में छह प्रतिशत बढ़कर 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा। नवंबर में घरेलू लेन-देन पर जीएसटी संग्रह में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। यह इस साल जीएसटी राजस्व में सबसे अच्छी मासिक वृद्धि है।

इस बार नवंबर में केंद्रीय जीएसटी से वसूली 19,592 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 27,144 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी से 49,028 करोड़ रुपये और जीएसटी उपकर से वसूली 7,727 करोड़ रुपये रही। एकीकृत जीएसटी में से 20,948 करोड़ रुपये आयात से वसूल हुए। इसी तरह उपकर की वसूली में 869 करोड़ रुपये आयातित माल पर उपकर से प्राप्त हुए। 30 नवंबर, 2019 तक अक्टूबर के महीने के लिए फाइल किये गये जीएसटीआर 3 बी रिटर्न की कुल संख्या 77.83 लाख है।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी को 25,150 करोड़ रुपये का और आईजीएसटी से एसजीएसटी को 17,431 करोड़ रुपये निपटान किया। नवंबर, 2019 के महीने में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 44,742 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 44,576 करोड़ रुपये है।

जुलाई 2017 में जीएसटी की स्थापना के बाद से यह आठवीं बार है कि मासिक संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसके अलावा, नवंबर 2019 का संग्रह जीएसटी की शुरुआत के बाद से तीसरा सबसे अधिक मासिक संग्रह है, जिससे आगे केवल अप्रैल 2019 और मार्च 2019 का संग्रह है। ■

2014 से भारतीय रक्षा उद्योग के साथ 1,96,000 करोड़ रुपये के 180 से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर

रक्षा मंत्रालय ने 2014 से भारतीय रक्षा उद्योग के साथ 1,96,000 करोड़ रुपये के 180 से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना शेष है। परियोजना पी17ए के अंतर्गत मिजोरम डॉकयार्ड लिमिटेड (एमडीएल) के साथ फरवरी 2015 में 45,000 करोड़ रुपये मूल्य के फ्रीगेट निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

परियोजना पी1135.6 के अंतर्गत 14,000 करोड़ रुपये मूल्य के दो फ्रीगेट के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध अक्टूबर 2018 में किए गए। भारतीय वायुसेना के लिए 41 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और भारतीय नौसेना के लिए 32 एएलएच बनाने के लिए हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मार्च 2017 और दिसंबर, 2017 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इन दोनों का संयुक्त मूल्य 14,100 करोड़ रुपये है। यह फरवरी 2015 में एचएएल के साथ 1100 करोड़ रुपये मूल्य के 14 ड्रोनियर 228 विमानों की खरीद के लिए किए गए अनुबंध के अतिरिक्त है।

अक्टूबर 2019 में बीईएल से 6,300 करोड़ रुपये मूल्य के आकाश मिसाइल प्रणाली के सात स्कवैड्रन तथा 7,900 करोड़ रुपये मूल्य की एकीकृत अग्रणी कमान तथा नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसीएस) खरीदने के लिए अनुबंध किए गए। ओएफबी से 19,100 करोड़ रुपये मूल्य के 464 टी-90एस/एसके टैंकों की सप्लाई के लिए मंत्रालय द्वारा नवंबर 2019 में अनुरोध किया गया है।

सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत मेसर्स एलएण्डटी से एक सौ 155 x 52 एमएम स्वचालित तोपें 4,300 करोड़ रुपये के मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। एयर फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिकीकरण (एमएएफआई) के लिए भारतीय वेंडरों के माध्यम से अनुबंध करने का कार्य अंतिम चरण में है।

सेना के तीनों अंगों ने भी टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, फोर्स मोटर्स प्रा.लि, टाटा पावर सेड, टेक महिन्द्रा लि., टाटा मोटर लि., अशोक लिलैंड लि., भारत फोर्ज लि., एमकेयू लि., एसएमपीपी दिल्ली और अल्फा डिजाइन से 1000 टन की ईंधन नौका, लाइट स्ट्राइक वाहन, पोर्टेबल डाइवर डिटेक्शन सोनर (पीडीडीएस), आरएफआईडी आधारित स्मार्ट कार्ड, सामग्री हैंडल करने वाले क्रेन के साथ 6x6 तथा 8x8 के हाई मोबिलिटी वाहन, डुअल टेक्नोलॉजी माइन डिटेक्टर, बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकट तथा एकीकृत तोप के लिए आदेश दिए हैं।

पी-75(1) पंडुब्बियों, नौसेना की उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर (एनयूएच) तथा भारतीय वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू जेट की खरीद की प्रक्रिया फंस जाने के कारण अब इन मामलों में एसपी मॉडल (डीपीपी-2016 के भाग के रूप में मई 2017 में लागू की गई खरीद प्रक्रिया) के अंतर्गत आगे काम किया जा रहा है। एसपी मॉडल के अंतर्गत मामलों को तेजी से निपटाया जा रहा है। यह पी-75(1) तथा एनयूएच के मामले में प्राप्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति से स्पष्ट होता है। यह मामले चयन के अंतिम चरण में हैं, जबकि 114 लड़ाकू विमानों के मामले में एसक्यूआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त मेक-II के अंतर्गत 44 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। रक्षा उत्कृष्टता (आईडीईएक्स) के लिए नवाचार के अंतर्गत 40 से अधिक स्टार्टअप नई टेक्नोलॉजी से संबंधित उत्पादों पर काम कर रहे हैं। ■

युद्ध में घायल सैनिकों के लिए सरकारी आवास की सुविधा को तीन माह से बढ़ाकर एक वर्ष करने की मंजूरी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से युद्ध में घायल सैनिकों के लिए सरकारी आवास सुविधा को तीन माह से बढ़ाकर एक वर्ष करने का निर्णय लिया। सशस्त्र बलों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की थी।

फिलहाल, मृत सैन्यकर्मियों का परिवार/उनकी विधवा दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास की सुविधा पाने के लिए अधिकृत हैं, जिसे 1999 एवं 2006 की नीतियों के अनुसार मामले की उपयुक्तता के आधार पर एक वर्ष और छह माह की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

जबकि, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान घायल होने और इस कारण से सेवा से अमान्य किए गए सैन्य कर्मियों के संदर्भ में सरकारी आवास की सुविधा केवल तीन माह की अवधि के लिए ही स्वीकृत है। ■

भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने की मंजूरी

देश में पहला कार्पोरेट बॉन्ड होगा भारत बॉन्ड ईटीएफ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 4 दिसंबर को भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बनाने और इसकी शुरुआत करने को मंजूरी दी। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू), केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई), केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (सीपीएफआई) और दूसरे सरकारी संगठनों के लिए पूंजी के अतिरिक्त स्रोत के तौर पर लाया गया है। भारत बॉन्ड ईटीएफ देश में पहले कार्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ होगा।

भारत बॉन्ड ईटीएफ की विशेषताएं

ईटीएफ सीपीएसई/सीपीएसयू/सीपीएफआई/दूसरे सरकारी संगठनों के बॉन्ड (शुरुआत में सभी एएए बॉन्ड) के बॉन्डस की बास्केट होगा।

- विनिमय पर व्यापार योग्य
- 1,000 रुपये की छोटी ईकाई
- पारदर्शी एनएवी (दिनभर एनएवी का सामयिक लाइव)
- पारदर्शी पोर्टफोलियो (वेबसाइट पर रोजाना प्रकाशन)
- कम लागत (0.0005%)

भारत बॉन्ड ईटीएफ का ढांचा

- प्रत्येक ईटीएफ की एक निर्धारित परिपक्वता तिथि होगी
- ईटीएफ जोखिम पुनरावृत्ति के आधार पर बुनियादी सूचकांक पर नजर रखेगा, यानी क्रेडिट गुणवत्ता और सूचकांक की औसत परिपक्वता का मिलान करेगा
- सीपीएसई, सीपीएसयू, सीपीएफआई अथवा दूसरे सरकारी संगठनों के बॉन्ड्स के ऐसे पोर्टफोलियो में निवेश करेगा, जो ईटीएफ की परिपक्वता अवधि से पहले अथवा उसी समय परिपक्व होंगे
- अभी तक इसमें दो परिपक्वता श्रेणियां है– तीन एवं 10 वर्ष। प्रत्येक श्रेणी में उसी परिपक्वता श्रेणी का एक अलग सूचकांक होगा

सूचकांक की कार्यप्रणाली

- सूचकांक का निर्माण एक स्वतंत्र सूचकांक प्रदाता – राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज- द्वारा किया जाएगा
- विशिष्ट परिपक्वता वर्षों– 3 एवं 10 वर्ष को ट्रैक करने वाले विभिन्न सूचकांक

निवेशकों को भारत बॉन्ड ईटीएफ का लाभ

- बॉन्ड ईटीएफ सुरक्षा (सीपीएसई और दूसरी सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए खास बॉन्ड), नकदी (विनिमय पर व्यापार योग्य) और अनुमानित कर कुशल रिटर्न उपलब्ध कराएगा।
- यह खुदरा निवेशकों को कम राशि के बॉन्ड्स (1,000 रुपये तक) में पहुंच उपलब्ध कराएगा, जिससे बॉन्ड बाजारों में आसान और कम लागत वाली पहुंच मिल सके।
- यह खुदरा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाएगा, जो नकदी और पहुंच में बाधाओं के चलते बॉन्ड बाजारों में भागीदारी नहीं करते हैं।
- कूपन के तौर बॉन्ड की तुलना में मामूली कर की दरों पर बॉन्ड, कर दक्षता लाते हैं। बॉन्ड ईटीएफ सूचीकरण के लाभ के साथ होते हैं, यह निवेशकों को होने वाले पूंजीगत लाभ पर टैक्स में काफी कमी लाता है।

सीपीएसई के लिए भारत बॉन्ड ईटीएफ के लाभ

- बॉन्ड ईटीएफ सीपीएसई, सीपीएसयू, सीपीएफआई और दूसरे सरकारी संगठनों को अपनी कर्ज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग वित्त व्यवस्था से अलग एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराता है।
- यह खुदरा और एचएनआई भागीदारी के जरिये उनके निवेशकों का आधार बढ़ाता है, जिससे उनके बॉन्ड की मांग बढ़ सकती है। बॉन्ड की मांग बढ़ने के साथ इसके जारीकर्ता कम लागत पर उधार लेने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे एक नियत समयावधि के लिए उधार लेने की उनकी लागत कम हो जाती है।
- विनिमय पर व्यापार से बॉन्ड ईटीएफ बुनियादी बॉन्ड्स के लिए बेहतर कीमत का पता लगाने में मदद करेगा।
- चूंकि सीपीएसई की उधार की जरूरतों का आकलन करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक व्यापक ऋण कैलेंडर तैयार और अनुमोदित किया जाएगा। यह कम से कम इस निवेश की सीमा तक सीपीएसई में उधार अनुशासन को विकसित करेगा।

बॉन्ड बाजारों पर प्रभाव

- नियत लक्ष्य वाले परिपक्वता बॉन्ड ईटीएफ से समूचे कैलेडर वर्ष में विभिन्न परिपक्वताओं के साथ एक मुनाफा श्रेणी और बॉन्ड ईटीएफ का सोपान बनने की उम्मीद है।
- ईटीएफ से भारत में नए बॉन्ड ईटीएफ को लेकर एक नया ईको-सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र – मार्केट मेकर्स, सूचकांक प्रदाता एवं निवेशकों में जागरुकता- बनने की उम्मीद है।
- इससे भारत में बॉन्ड ईटीएफ का दायरा बढ़ने की संभावना है। इससे व्यापक स्तर पर प्रमुख उद्देश्यों - बॉन्ड बाजारों को मजबूत बनाने, खुदरा भागीदारी को बढ़ाने और उधार लेने की लागत को कम करने- को हासिल किया जा सकेगा। ■

समाज की सर्वांगीण उन्नति हमारा ध्येय

दीनदयाल उपाध्याय

माननीय रज्जू भैया ने हमें यह बताया था कि एक ऐसी परंपरा हम देश में निर्माण करना चाहते हैं कि जो सत्ता से अलिप्त रहते हुए उसके ऊपर अंकुश रखते हुए सतत चलती जाए और इस प्रकार सत्ता को सही मार्ग पर चला सके। हमें परंपरा के उस स्वरूप का विचार करना पड़ेगा। साथ ही हम जिनका नियंत्रण करना चाहते हैं, जिनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, उसका भी थोड़े-बहुत अंशों में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमें इसके स्वरूप का ठीक प्रकार से ज्ञान न रहा तो आख़िर हम नियंत्रण क्या करेंगे? सत्ता को किस दिशा में ले जाएंगे?

नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, जैसाकि कहा है-'अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः' कि अगर अंधे को अंधा ही मार्ग दिखाए, तो वह उसे कहां ले जाएगा? संभवतया गड्ढे में पटक देगा। तो उस नाते से हमें इस बात का कुछ-न-कुछ विचार अवश्य ही करना पड़ेगा कि हम संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो हम संपूर्ण समाज को किधर ले जाएंगे? समाज के भिन्न-भिन्न अंग हैं। समाज के कल्याण की दृष्टि से जो उसके भिन्न-भिन्न साधन हैं, वे साधन किस प्रकार से काम करेंगे, उनका ध्येय कौन सा होगा? इन सब बातों का हमें कम-से-कम स्वयं विचार करना चाहिए। इनका हमें स्वयं ज्ञान होना चाहिए, जिनसे कि हम अलिप्त रह सकते हैं। वैद्य तो स्वयं औषधि नहीं लेता किंतु रोगी के संबंध में वैद्य को पूरे तरीके से पता रहता है, साथ ही औषधि के गुणदोषों का भी उसको ज्ञान रहता है। फिर उसको यह आवश्यक नहीं कि वह स्वयं औषधि ले। संभवतः उसे औषधि लेनी ही नहीं चाहिए, जो वैद्य स्वयं औषधि लेने लग जाएगा और सोचेगा कि यह औषधि तो बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है, इसे रोगी को न देकर मैं स्वयं ही खा लूं तो अच्छा रहेगा। अब जब वह वैद्य रोगी के बदले उस मीठी औषधि को स्वयं ही खाने लगेगा, सोचो कि उस वैद्य का क्या होगा? रोगी तो मरेगा ही, लेकिन शायद वह वैद्य भी नहीं बचेगा। तो इसलिए यह औषधि स्वयं लेने की आवश्यकता नहीं, किंतु उन औषधियों के गुण-दोष से परिचित होना आवश्यक है। रोगी के संबंध में भी थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। तभी जाकर वह उस रोगी को ठीक कर सकेगा।

इसी प्रकार हमें समाज के सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है कि इस समाज को हम कहां ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं? जब हम इस बात का विचार करते हैं तो हमें पहले यह सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ध्येय होना चाहिए, जिस ध्येय की ओर हम स्वयं चलेंगे, जिस ध्येय की ओर हम दूसरों को चलाएंगे, उन्हें चलने की प्रेरणा देंगे। इस बात का विचार करें कि आख़िर हम चाहते क्या हैं? नहीं तो अनेक बार लोग कह सकते हैं कि भाई, संघ के लोग क्या काम करते हैं? यह संघ के लोग अपनी शाखाएं लगा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, समता वगैरह का कार्यक्रम कर लेते हैं, राइट-लेफ्ट कर लेते हैं, बाक़ी और इसमें क्या है? हम लोग इस बात के संबंध में अधिक आग्रह भी करते हैं और लोगों से कहते हैं कि शाखा पर आओ और शाखा के हमारे जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को करो। यह आग्रह हमारा सही है, आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा ही हम जिस चीज़ को चाहते हैं, जिस अवस्था को चाहते हैं, उस अवस्था का निर्माण करना संभव होगा।

इस आग्रह के परिणामस्वरूप बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि इतना ही इनका काम है। अगर इतना ही हमारा काम है तो अंत में हम क्या इस समाज की ऐसी अवस्था की कल्पना करते हैं कि लोगों को केवल शाम-सबह शाखा पर आकर खेल-कद और थोड़े-बहुत कार्यक्रम करने के बाद आराम से सारा दिन घर पर बैठना चाहिए? क्या इस अवस्था को आदर्श अवस्था कह सकते हैं? ऐसी अवस्था के बाद बाक़ी का कुछ करने को नहीं रहेगा। इसलिए इन बातों पर हमें विचार करना ही पड़ेगा कि हमारा ध्येय क्या है? जब हम विचार करते हैं तो हमारा ध्येय निश्चित हो जाता है।

संघ के हर स्वयंसेवक को पता है, जब हम प्रतिज्ञा लेते हैं, तब अपने इस ध्येय का उच्चारण करते हैं कि हम अपने समाज की सर्वांगीण उन्नति चाहते हैं। समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए ही हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटक बने हैं। हमने समाज का कोई भी क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा। कोई क्षेत्र अधूरा या हमसे अछूता नहीं है। समाज में जितनी भी चीजें हैं, उन सब चीज़ों पर हम लोग विचार करके चलते हैं, क्योंकि हमें सब प्रकार की उन्नति करनी है।

इस उन्नति के साथ-साथ हमने थोड़ा सा

संघ के हर स्वयंसेवक को पता है, जब हम प्रतिज्ञा लेते हैं, तब अपने इस ध्येय का उच्चारण करते हैं कि हम अपने समाज की सर्वांगीण उन्नति चाहते हैं। समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए ही हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटक बने हैं।

उसका स्वरूप भी सोचा है। उन्नति शब्द कहना सरल है और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जो यह कहेगा कि उसे यह उन्नति नहीं चाहिए। जो काम करने के लिए आगे बढ़ा है, वह तो यही कहेगा कि ठीक है, मैं सब कुछ चाहूंगा और सब प्रकार की उन्नति करूंगा, सब प्रकार से समाज को आगे ले जाऊंगा। आज भी देश में जो-जो लोग काम कर रहे हैं और वे किसी भी मार्ग से चल रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता हो कि हम समाज को अधूरा छोड़कर चलेंगे। वह तो समाज की सब प्रकार की उन्नति करने का दावा करते हैं। इसलिए हमने इस बात की थोड़ी सी व्याख्या की है।

व्याख्या करते समय हमने यह कहा है कि हमारी जो समाज की उन्नति होगी, उसमें यहां का समाज, यहां की संस्कृति, यहां का धर्म, उसका संरक्षण करके हम समाज की उन्नति करेंगे। हमने दोनों को एक-दूसरे के साथ जोड़ दिया है। अपने धर्म और संस्कृति को हटाकर समाज की उन्नति की कोई कल्पना हमारे सामने नहीं आती। हमारे सामने तो समाज की उन्नति की वह कल्पना आती है, जिसमें हमारे धर्म और संस्कृति का आधार रहेगा। धर्म और संस्कृति का संरक्षण होगा, वही हमारी उन्नति है। जिसमें धर्म और संस्कृति का संरक्षण नहीं होगा, उसको हम उन्नति मानकर ही नहीं चलें।

यही बात रोज़ अपनी प्रार्थना में भी कहते हैं, वहां भगवान् से जब मांगते हैं तो अपनी प्रार्थना के अंत में यह भाव हम व्यक्त करते हैं कि हमारी यह जो विजयशालिनी संघ शक्ति है, वह इस राष्ट्र के धर्म का संरक्षण कर हमें परम वैभव के पद पर ले जाने में आपके आशीर्वाद से सफल हो। हम मांगते हैं कि परम वैभव और सर्वांगीण उन्नति में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जब सर्वांगीण उन्नति होगी तो हमें परम वैभव प्राप्त हो जाएगा। हमें बाक़ी के वैभव नहीं चाहिए। राष्ट्र के धर्म का संरक्षण करके हमें यह वैभव मिलना चाहिए। राष्ट्र के धर्म को छोड़कर, उसका विनाश कर, उसे भुलाकर हमें परम वैभव मिले तो हम कहेंगे कि ऐसा परम वैभव ठीक नहीं है।

तो वास्तविकता यह है कि हमारा जो ध्येय रहता है, उसे लेकर ही हम बाक़ी की बातों पर विचार करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी उन्नति हो जानी चाहिए। वे यह नहीं सोचते कि उन्नति के लिए कुछ-न-कुछ आधार चाहिए। यानी राष्ट्र का धर्म जो कि इस उन्नति का आधार है। इस बात का वे लोग विचार नहीं करते, केवल उन्नति ही चाहते हैं कि जैसे पेट भर जाए, परंतु भोजन न करना पड़े। अगर ऐसी कोई कल्पना हो कि पेट भर जाए और भोजन न करना पड़े या फिर शक्ति आ जाए और उसके लिए कोई व्यायाम न करना पड़े। बाक़ी हाथ-पैरों के अंदर जो कछ थोड़ा-बहुत रक्त है। वह भी किसी प्रकार न प्रकट हो और बल आ जाए। यह संभव नहीं है। हालांकि दोनों की उन्नति का राष्ट्र के धर्म के साथ घनिष्ठता का संबंध है। इन दोनों को हटाकर विचार नहीं कर सकते। किंतु बाक़ी के लोग जो धर्म का विचार नहीं करते और विचार केवल इस बात का करते हैं कि हमारे राष्ट्र का वैभव हो जाए।

हमारी जो समाज की उन्नति होगी, उसमें यहां का समाज, यहां की संस्कृति, यहां का धर्म, उसका संरक्षण करके हम समाज की उन्नति करेंगे। हमने दोनों को एक-दूसरे के साथ जोड़ दिया है। अपने धर्म और संस्कृति को हटाकर समाज की उन्नति की कोई कल्पना हमारे सामने नहीं आती।

इस धर्म का विचार न करते हुए चलने वाले भी दो प्रकार के लोग हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है। वे धर्म को वैभव के लिए आवश्यक नहीं समझते, अनावश्यक भी नहीं मानते और कहते हैं कि रहा तो ठीक, न रहा तो ठीक। इसका वैभव के साथ कोई संबंध नहीं। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं, जो राष्ट्र के वैभव के लिए धर्म को अनावश्यक ही नहीं, हानिकर मानते हैं और ऐसा समझकर चलते हैं कि राष्ट्र को यदि वैभव प्राप्त करना है तो इसका जो धर्म चला आ रहा है, इस धर्म को समाप्त करना पड़ेगा। इसे नष्ट करना पड़ेगा, इसे नष्ट करके ही राष्ट्र को वैभव प्राप्त होगा। जब तक राष्ट्र का यह धर्म चलता रहेगा, तब तक किसी भी प्रकार से वैभव प्राप्त नहीं होगा, ऐसा विचार करनेवाले लोग हैं।

ये जो दो प्रकार के विचार वाले लोग हैं, कहना पड़ेगा कि वास्तव में उन्होंने शायद धर्म के स्वरूप को भी नहीं समझा। उनके सामने वैभव की कल्पना भी किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं है। इसलिए वे बेचारे अज्ञान के कारण ऐसा सोचकर चलते हैं कि यह धर्म जो है, हानिकारक है। धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, इसे समाप्त कर देंगे तभी शायद इसका वैभव प्राप्त होगा। यह एक उलटा ही विचार करनेवाली चीज़ है। जैसे कि कोई अग्नि के बारे में विचार करे कि अग्नि बड़ी प्रज्वलित हो जाए, परंतु उसमें दाहकता न रहे। तो यह कैसे हो सकता है? बिना दाहकता के अग्नि कभी प्रज्वलित नहीं हो सकती। अग्नि यदि प्रज्वलित होगी तो उसके अंदर दाहकता रहेगी ही, क्योंकि दाहकता अग्नि का धर्म है। यदि दाहकता को निकाल दिया और दाहकता निकालने के बाद हमने यदि अग्नि का विचार किया तो फिर वह अग्नि अग्नि नहीं रहेगी।

उसी प्रकार से राष्ट्र को जो कुछ भी धर्म है, उस धर्म को निकालकर यदि हम सोचेंगे तो फिर हमारे सामने बड़ी समस्या हो जाएगी। यहां तक कि हमारा वैभव कहां है? वैभव क्या है? इसका भी हम ठीक प्रकार से निर्धारण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आख़िर को यह भी तो बड़ा महत्त्व का प्रश्न है कि वैभव क्या है, किसको हम वैभव कहेंगे? किस अवस्था को वैभव माना जाए। यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर साधारणतया नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर देने के लिए वास्तव में जिसे धर्म की कल्पना है, जिसको राष्ट्र की प्रकृति की कल्पना है, जिसे राष्ट्र क्या है, इसका पता है, जो इस राष्ट्र को पहचानता है, जो इस राष्ट्र की आत्मा को पहचानता है, वास्तव में वही उसके वैभव का विचार कर सकेगा। जिसको राष्ट्र का पता नहीं है, वह उसके वैभव का विचार भी क्या कर सकेगा? ■ क्रमशः...

— पाञ्चजन्य, मई २६, 1961, संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : लखनऊ

कमल संदेश संपादकीय बोर्ड के सदस्य सत्यपाल जी का निधन

कमल संदेश के संपादकीय बोर्ड के सदस्य श्री सत्यपाल का निधन 2 दिसंबर, 2019 को वसुंधरा, गाजियाबाद में हुआ। वह 90 साल के थे।

इससे पहले वह साल 1992 में भाजपा समाचार से जुड़े। बाद में उन्होंने इस पत्रिका के संपादक पद को भी सुशोभित किया। भाजपा समाचार से जुड़ने से पूर्व वह गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका पुलिस विज्ञान के संपादक के रूप में कार्यरत रहे। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और दामाद हैं। ■

कमल संदेश परिवार
की ओर से श्री सत्यपाल के निधन पर
उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि!

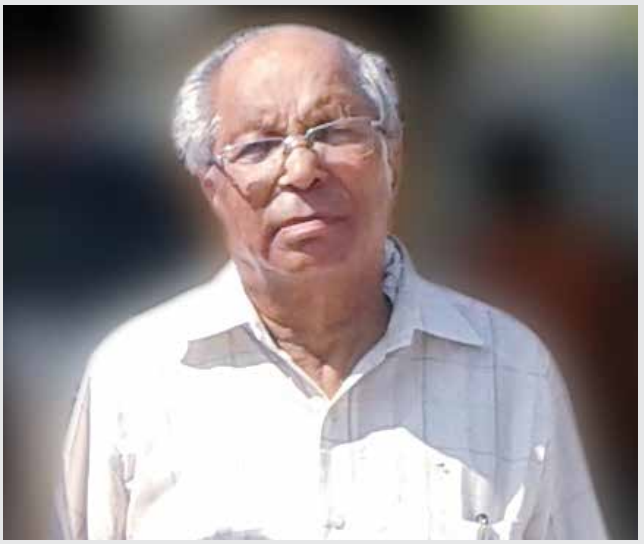

तीन महीने से कम समय में 3.8 लाख गो-जातीय पशुओं का बीजारोपण

3.7 लाख से अधिक किसान लाभान्वित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 11 सितंबर, 2019 को घोषित नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों सहित 6,000 चुने गए जिलों को कवर करने वाला राष्ट्रव्यापी कृत्रिम बीजारोपण कार्यक्रम (एनएआईपी) ने गति पकड़ ली है। कृत्रिम बीजारोपण दर लगातार बढ़ रही है और यह दर अब प्रतिदिन 25,000 पशु हो गई है। एनएआईपी अभियान का उद्देश्य सभी नस्ल की गो-जातियों को कवर करना है, ताकि कम लागत की प्रजनन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके। कृत्रिम बीजारोपण के लाभ लगभग तीन वर्ष में दिखते हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 29 नवंबर, 2019 तक 3.8 लाख कृत्रिम बीजारोपण का कार्य किया गया है, जिससे 3.7 लाख से अधिक किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य 6 महीनों में एक करोड़ से ऊपर गो-जातियों के बीजारोपण तथा उनके कान में पशुआधार टैग पहनाना है। कृत्रिम बीजारोपण के अंतर्गत सभी गाय और भैंस को पशुधन टैग लगाया जाएगा, ताकि पशु उत्पादकता तथा स्वास्थ्य (आईएनएपीएच) डाटा बेस पर उनकी सूचना देखी जा सके।

कार्यक्रम में शामिल होने वाले 28 राज्यों में से उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं- तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड तथा झारखंड। पीछे रहने वाले राज्यों में- छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश हैं। पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम अभी शुरू होना है। सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य पीछे हैं और इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। समग्र रूप से चुनिंदा जिलों में कृत्रिम बीजारोपण कवरेज के 18 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत होने का अनुमान है। ■

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने मालदीव में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

भारत में निर्मित तटरक्षक जहाज 'कामयाब' मालदीव को मिला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने 4 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मालदीव में अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

भारत में निर्मित तटरक्षक जहाज 'कामयाब' को उपहार के तौर पर मालदीव को देना, रुपे कार्ड लॉन्च करना, एलईडी लाइटों का उपयोग कर माले को रोशन करना, व्यापक सकारात्मक असर वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं और मछली प्रसंस्करण संयंत्रों को लॉन्च करना इनमें शामिल हैं।

राष्ट्रपति श्री सालेह को उनके कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा होने पर उन्हें बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह भारत-मालदीव संबंधों के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और मालदीव की 'पहले भारत' नीति ने सभी सेक्टरों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है।

फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट तटरक्षक जहाज 'कामयाब' का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे मालदीव की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) तथा पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

श्री मोदी ने द्वीप में रहने वाले समुदाय की आजीविका में सहयोग देने के लिए 'व्यापक सकारात्मक असर वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं' के जरिए साझेदारी करने पर खुशी जताई।

प्रधानमंत्री ने यह बात रेखांकित की कि 'दोनों देशों की जनता के बीच आपसी संपर्क' भी भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मालदीव में भारत के पर्यटकों का आंकड़ा दोगुने से भी अधिक हो गया है। यही नहीं, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू से तीन सीधी उड़ानें इसी सप्ताह शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि रुपे भुगतान व्यवस्था की शुरुआत से भारतीयों के लिए मालदीव यात्रा और भी सुगम हो जाएगी।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार हुलहुलमाले में एक कैंसर अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर भी काम कर रही है। वहीं, 34 द्वीपों में जल एवं स्वच्छता परियोजना पर भी जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा।

प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने एवं विकास की गति तेज करने के लिए मालदीव के साथ साझेदारी को जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों ही देश हिंद महासागर क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। ■

मेरे अटल जी

नरेन्द्र मोदी

अटल जी अब नहीं रहे। मन नहीं मानता। अटल जी, मेरी आंखों के सामने हैं, स्थिर हैं। जो हाथ मेरी पीठ पर धौल जमाते थे, जो स्नेह से, मुस्कराते हुए मुझे अंकवार में भर लेते थे, वे स्थिर हैं। अटल जी की ये स्थिरता मुझे झकझोर रही है, अस्थिर कर रही है। एक जलन सी है आंखों में, कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पा रहा। मैं खुद को बार-बार यकीन दिला रहा हूं कि अटल जी अब नहीं हैं, लेकिन ये विचार आते ही खुद को इस विचार से दूर कर रहा हूं। क्या अटल जी वाकई नहीं हैं? नहीं। मैं उनकी आवाज अपने भीतर गूंजते हुए महसूस कर रहा हूं, कैसे कह दूं, कैसे मान लूं, वे अब नहीं हैं।

वे पंचतत्व हैं। वे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सबमें व्याप्त हैं, वे अटल हैं, वे अब भी हैं। जब उनसे पहली बार मिला था, उसकी स्मृति ऐसी है जैसे कल की ही बात हो। इतने बड़े नेता, इतने बड़े विद्वान। लगता था जैसे शीशे के उस पार की दुनिया से निकलकर कोई सामने आ गया है। जिसका इतना नाम सुना था, जिसको इतना पढ़ा था, जिससे बिना मिले, इतना कुछ सीखा था, वो मेरे सामने थे। जब पहली बार उनके मुंह से मेरा नाम निकला तो लगा, पाने के लिए बस इतना ही बहुत है। बहुत दिनों तक मेरा नाम लेती हुई उनकी वह आवाज मेरे कानों से टकराती रही। मैं कैसे मान लूं कि वह आवाज अब चली गई है।

कभी सोचा नहीं था, कि अटल जी के बारे में ऐसा लिखने के लिए कलम उठानी पड़ेगी। देश और दुनिया अटल जी को एक स्टेट्समैन, धारा प्रवाह वक्ता, संवेदनशील कवि, विचारवान लेखक, धारदार पत्रकार और विजनरी जननेता के तौर पर जानती है, लेकिन मेरे लिए उनका स्थान इससे भी ऊपर का था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे उनके साथ बरसों तक काम करने का अवसर मिला, बल्कि मेरे जीवन, मेरी सोच, मेरे आदर्शों-मूल्यों पर जो छाप उन्होंने छोड़ी, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया, उसने मुझे गढ़ा है, हर स्थिति में अटल रहना सिखाया है।

हमारे देश में अनेक ऋषि, मुनि, संत आत्माओं ने जन्म लिया है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक की विकास यात्रा के लिए भी असंख्य लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की रक्षा और 21वीं सदी के सशक्त, सुरक्षित भारत के लिए अटल जी ने जो किया, वह अभूतपूर्व है।

उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, बाकी सब का कोई महत्त्व नहीं। इंडिया फर्स्ट –भारत प्रथम, ये मंत्र वाक्य उनका जीवन ध्येय था। पोखरण देश के लिए जरूरी था तो चिंता नहीं की प्रतिबंधों और आलोचनाओं की, क्योंकि देश प्रथम था। सुपर कंप्यूटर नहीं मिले, क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिले तो परवाह नहीं, हम खुद बनाएंगे, हम खुद अपने दम पर अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक कुशलता के बल पर असंभव दिखने वाले कार्य संभव कर दिखाएंगे और ऐसा किया भी। दुनिया को चकित किया। सिर्फ एक ताकत उनके भीतर काम करती थी- देश प्रथम की जिद।

काल के कपाल पर लिखने और मिटाने की ताकत, हिम्मत और चुनौतियों के बादलों में विजय का सूरज उगाने का चमत्कार उनके सीने में था, तो इसलिए क्योंकि वह सीना देश प्रथम के लिए धड़कता था। इसलिए हार और जीत उनके मन पर असर नहीं करती थी। सरकार बनी तो भी, सरकार एक वोट से गिरा दी गयी तो भी, उनके स्वरों में पराजय को भी विजय के ऐसे गगनभेदी विश्वास में बदलने की ताकत थी कि जीतने वाला ही हार मान बैठे।

अटल जी कभी लीक पर नहीं चले। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नए रास्ते बनाए और तय किए। "आंधियों में भी दीये जलाने" की क्षमता उनमें थी। पूरी बेबाकी से वे जो कुछ भी बोलते थे, सीधा जनमानस के हृदय में उतर जाता था। अपनी बात को कैसे रखना

है, कितना कहना है और कितना अनकहा छोड़ देना है, इसमें उन्हें महारत हासिल थी।

राष्ट्र की जो उन्होंने सेवा की, विश्व में मां भारती के मान-सम्मान को उन्होंने जो बुलंदी दी, इसके लिए उन्हें अनेक सम्मान भी मिले। देशवासियों ने उन्हें भारत रत्न देकर अपना मान भी बढ़ाया। लेकिन वे किसी भी विशेषण, किसी भी सम्मान से ऊपर थे।

जीवन कैसे जीया जाए, राष्ट्र के काम कैसे आया जाए, यह उन्होंने अपने जीवन से दूसरों को सिखाया। वे कहते थे, "हम केवल अपने लिए ना जीएं, औरों के लिए भी जीएं...हम राष्ट्र के लिए अधिकाधिक त्याग करें। अगर भारत की दशा दयनीय है तो दुनिया में हमारा सम्मान नहीं हो सकता, किंतु यदि हम सभी दृष्टियों से सुसंपन्न हैं तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी"

देश के गरीब, वंचित, शोषित के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वे जीवन भर प्रयास करते रहे। वे कहते थे "गरीबी, दरिद्रता गरिमा का विषय नहीं है, बल्कि यह विवशता है, मजबूरी है और विवशता का नाम संतोष नहीं हो सकता।" करोड़ों देशवासियों को इस विवशता से बाहर निकालने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। गरीब को अधिकार दिलाने के लिए देश में आधार जैसी व्यवस्था, प्रक्रियाओं का ज्यादा से ज्यादा सरलीकरण, हर गांव तक सड़क, स्वर्णिम चतुर्भुज, देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्र निर्माण के उनके संकल्पों से जुड़ा था।

आज भारत जिस टेक्नोलॉजी के शिखर पर खड़ा है उसकी आधारशिला अटल जी ने ही रखी थी। वे अपने समय से बहुत दूर तक देख सकते थे - स्वप्नद्रष्टा थे लेकिन कर्मवीर भी थे। कवि हृदय, भावुक मन के थे तो पराक्रमी सैनिक मन वाले भी थे। उन्होंने विदेश की यात्राएं कीं। जहां-जहां भी गए, स्थाई मित्र बनाये और भारत के हितों की स्थाई आधारशिला रखते गए। वे भारत की विजय और विकास के स्वर थे।

अटल जी का प्रखर राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए समर्पण करोड़ों देशवासियों को हमेशा से प्रेरित करता रहा है। राष्ट्रवाद उनके लिए सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि जीवन शैली थी। वे देश को सिर्फ एक भूखंड, ज़मीन का टुकड़ा भर नहीं मानते थे, बल्कि एक जीवंत, संवेदनशील इकाई के रूप में देखते थे। "भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रपुरुष है।" यह सिर्फ भाव नहीं, बल्कि उनका संकल्प था, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। दशकों का सार्वजनिक जीवन उन्होंने अपनी इसी सोच को जीने में, धरातल पर उतारने में लगा दिया। आपातकाल ने हमारे लोकतंत्र पर जो दाग लगाया था उसको मिटाने के लिए अटल जी के प्रयास को देश हमेशा याद रखेगा।

देश के गरीब, वंचित, शोषित के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अटलजी जीवन भर प्रयास करते रहे। वे कहते थे "गरीबी, दरिद्रता गरिमा का विषय नहीं है, बल्कि यह विवशता है, मजबूरी है और विवशता का नाम संतोष नहीं हो सकता।" करोड़ों देशवासियों को इस विवशता से बाहर निकालने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। गरीब को अधिकार दिलाने के लिए देश में आधार जैसी व्यवस्था, प्रक्रियाओं का ज्यादा से ज्यादा सरलीकरण, हर गांव तक सड़क, स्वर्णिम चतुर्भुज, देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्र निर्माण के उनके संकल्पों से जुड़ा था।

राष्ट्रभक्ति की भावना, जनसेवा की प्रेरणा उनके नाम के ही अनुकूल अटल रही। भारत उनके मन में रहा, भारतीयता तन में। उन्होंने देश की जनता को ही अपना आराध्य माना। भारत के कण-कण, कंकर-कंकर, भारत की बूंद-बूंद को, पवित्र और पूजनीय माना।

जितना सम्मान, जितनी ऊंचाई अटल जी को मिली उतना ही अधिक वह ज़मीन से जुड़ते गए। अपनी सफलता को कभी भी उन्होंने अपने मस्तिष्क पर प्रभावी नहीं होने दिया। प्रभु से यश, कीर्ति की कामना अनेक व्यक्ति करते हैं, लेकिन ये अटल जी ही थे जिन्होंने कहा,

"हे प्रभु! मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना। गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना"

अपने देशवासियों से इतनी सहजता और सरलता से जुड़े रहने की यह कामना ही उनको सामाजिक जीवन के एक अलग पायदान पर खड़ा करती है।

वे पीड़ा सहते थे, वेदना को चुपचाप अपने भीतर समाये रहते थे, पर सबको अमृत देते रहे- जीवन भर। जब उन्हें कष्ट हुआ तो कहने लगे- "देह धरण को दंड है, सब काहू को होये, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूरख भुगते रोए।" उन्होंने ज्ञान मार्ग से अत्यंत गहरी वेदनाएं भी सहन कीं और वीतरागी भाव से विदा ले गए।

यदि भारत उनके रोम-रोम में था तो विश्व की वेदना उनके मर्म को भेदती थी। इसी वजह से हिरोशिमा जैसी कविताओं का जन्म हुआ। वे विश्व नायक थे। मां भारती के सच्चे वैश्विक नायक। भारत की सीमाओं के परे भारत की कीर्ति और करुणा का संदेश स्थापित करने वाले आधुनिक बुद्ध।

कुछ वर्ष पहले लोकसभा में जब उन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से सम्मानित किया गया था तब उन्होंने कहा था, "यह देश बड़ा अद्भुत है, अनूठा है। किसी भी पत्थर को सिंदूर लगाकर अभिवादन किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा सकता है।"

अपने पुरुषार्थ को, अपनी कर्तव्यनिष्ठा को राष्ट्र के लिए समर्पित करना उनके व्यक्तित्व की महानता को प्रतिबिंबित करता है। यही सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए उनका सबसे बड़ा और प्रखर संदेश है। देश के साधनों, संसाधनों पर पूरा भरोसा करते हुए, हमें अब अटल जी के सपनों को पूरा करना है, उनके सपनों का भारत बनाना है।

नए भारत का यही संकल्प, यही भाव लिए मैं अपनी तरफ से और सवा सौ करोड़ देशवासियों की तरफ से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

हमारे संविधान में समावेशन की शक्ति है: नरेन्द्र मोदी

हमारे लिए सबसे पवित्र पुस्तक है हमारा संविधान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे संविधान में समावेशन की ऐसी शक्ति है, जो हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ राष्ट्र की एकता कायम रखने में समर्थ बनाती है।

प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस के बारे में बताया कि कुछ अवसर ऐसे हैं जो अतीत के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाते हैं। ये हमें बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिवस है। आज से 70 वर्ष पूर्व हमने अपने महान संविधान को विधिवत लागू किया था।

श्री मोदी ने संविधान को एक ऐसा सार बताया, जो संविधान सभा के कई विचार-विमर्शों के बाद संभव हुआ। उन्होंने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश के लिए संविधान प्रदान करने के लिए प्रयास किए।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'इस केंद्रीय कक्ष में सात दशक पूर्व हमारे सपनों, चुनौतियों और परिदृश्यों के आधार पर संविधान के प्रत्येक वाक्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विस्तृत विचार-विमर्श किए और हमें यह विरासत सौंपी। मैं उन सभी महानुभावों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमें यह संविधान सौंपने के लिए कार्य किए थे।'

श्री मोदी ने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों के सपनों ने हमारे संविधान में निहित शब्दों और मूल्यों के रूप में आकार ग्रहण किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान पर अपने अंतिम भाषण में लोगों को स्मरण कराया था कि अतीत में अपनी गलतियों के कारण हमने देश की स्वतंत्रता और गणतांत्रिक प्रकृति दोनों को खो दिया था।

श्री मोदी ने कहा कि अम्बेडकर जी ने लोगों को सचेत करते हुए पूछा था कि क्या देश अब अपनी स्वतंत्रता और अपने लोकतंत्र को बरकरार रख सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर बाबासाहेब अम्बेडकर आज जीवित होते, तो शायद बहुत खुश होते। भारत ने अपने गुणों को बरकरार रखने के साथ-साथ लोकतंत्र और स्वतंत्रता

को भी मजबूत किया।

श्री मोदी ने कहा, 'यही कारण है कि मैं विधानमंडल, कार्यपालिका और संविधान के न्यायिक विभागों को नमन करता हूं, जो इसमें उल्लिखित मूल्यों एवं आदर्शों को संरक्षित करने में मददगार हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि वह संविधान को कायम रखने के लिए पूरे देश का भी नमन करते हैं।

श्री मोदी ने कहा, 'मैं उन 130 करोड़ भारतीयों को नमन करता हूं, जिनका भारत के लोकतंत्र में विश्वास कभी कम नहीं हुआ और जिन्होंने हमेशा पवित्र पुस्तक और मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में संविधान का सम्मान किया। हमारे संविधान के 70 साल हमारे लिए खुशियाली, सर्वोच्चता और निष्पादन की भावना पैदा करते हैं। यह खुशहाली हमारे संविधान के गुणों के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़े होने के कारण है। देश के लोगों ने इसके विपरीत किसी भी प्रयास को अस्वीकार कर दिया है।

उन्होंने कहा कि संविधान के आदर्शों के कारण सर्वोच्चता की भावना है, जिसके बल पर हम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की ओर बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने संविधान को पवित्र पुस्तक बताते हुए कहा कि हमारा निष्कर्ष यह है कि संविधान ही एकमात्र साधन है, जिसके माध्यम से यह विशाल और विविधतापूर्ण देश अपनी आकांक्षाओं, सपनों और प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है।

उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमारे लिए सबसे पवित्र पुस्तक है, जो हमारे जीवन, हमारे समाज, हमारी परंपराओं, हमारे मूल्यों का सम्मिश्रण होने के साथ-साथ हमारी सभी चुनौतियों का समाधान भी है।

उन्होंने कहा कि हमारा संविधान गरिमा और एकता के दोहरे दर्शन पर आधारित है। संविधान के दो मंत्र 'भारतीयों के लिए गरिमा' और 'भारत के लिए एकता' हैं। इसने भारत की एकता को अक्षुण्ण रखते हुए हमारे नागरिकों की गरिमा को सर्वोपरि रखा।

प्रधानमंत्री ने संविधान को विश्वभर के लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या बताई और कहा कि यह हमें अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के बारे में भी सचेत करता है। 'भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों को भी उल्लेख किया गया है। यह हमारे संविधान का एक विशेष पहलू है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अधिकारों और कर्तव्यों के बीच के संबंध और संतुलन को बहुत अच्छी तरह समझते थे।'

उन्होंने लोगों से संविधान में निहित कर्तव्य का पालन करने की भावना विकसित करने का आग्रह किया।

श्री मोदी ने कहा, 'आइए हम इस बारे में सोचें कि हम अपने संविधान में निहित कर्तव्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं। हमें सेवा और कर्तव्य के बीच अंतर को समझना चाहिए। जबकि सेवा स्वैच्छिक है, यानी आप सड़क पर किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं तो आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। यह हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोगों के साथ बातचीत में कर्तव्यों पर जोर दें।'

श्री मोदी ने कहा, 'भारत के गौरवशाली नागरिकों के रूप में, आइए हम इस बारे में सोचें कि कैसे हमारे कार्यों से हमारा देश और भी मजबूत होगा।'

उन्होंने कहा, "हमारा संविधान 'हम भारत के लोग' से शुरू होता है। आइए हम महसूस करें कि हम लोग इसकी ताकत, इसकी प्रेरणा और इसका उद्देश्य हैं।" प्रधानमंत्री ने इस दिन को उस दिन के रूप में भी याद किया, जब 2008 में मुंबई में एक आतंकवादी हमले में कई लोग मारे गए थे। उन्होंने उस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री मोदी ने कहा, "लेकिन आज एक ऐसा दिन भी है, जो दर्द का कारण बनता है, जब 26 नवंबर को मुंबई में आतंकवादियों ने वसुधैव कुटुम्बकम (एक विश्व एक परिवार) के हजारों वर्ष पुराने उस समृद्ध दर्शन को नष्ट करने की कोशिश की है। मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।" ■

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून सभी के लिए बराबर है: अमित शाह

राज्य सभा

विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद में 3 दिसंबर को पारित हो गया। यह विधेयक 27 नवंबर को लोक सभा में पारित हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य सभा में बोलते हुए कहा कि यह बिल एक परिवार को ध्यान में रखकर नहीं लाया जा रहा है। उनका कहना था कि गांधी परिवार की सुरक्षा और एसपीजी की सुरक्षा के बीच में कोई संबंध नहीं है। उनके लिए पहले ही जेड प्लस (एएसएल, एंबुलेंस की सुविधा के साथ) सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है, जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। उनका कहना था कि एसपीजी के बिल में यह पांचवा संशोधन एक परिवार के कारण नहीं है, बल्कि पहले चार परिवर्तन एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे।

श्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में बारी-बारी आना जाना पड़ता है उसे स्वीकार भी करना पड़ता है। देश में 130 करोड़ लोग अपना वोट डालते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा फिर प्रधानमंत्री तय होता है और आज यह सच है कि श्री नरेन्द्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं।

श्री शाह ने कहा कि केवल गांधी परिवार ही नहीं, गांधी परिवार सहित 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और उसका निर्वहन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु किसी को एसपीजी ही चाहिए यह जिद ठीक नहीं है। उनका कहना था कि एसपीजी का गठन विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को लेकर किया जाता है।

उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि गांधी परिवार के तीनों सुरक्षा प्राप्तकर्ताओं को वही सुरक्षा जवान दिए गए हैं, जो किसी न किसी रूप में एसपीजी में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। श्री शाह ने कहा कि एसपीजी को स्टेटस सिंबल न बनाया जाय। गांधी परिवार को देश के नागरिक को मिलने वाली सर्वोच्च सुरक्षा दी गई है जो कि देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री व अन्य के पास है, लेकिन उनकी ये मांग के उन्हे एसपीजी सुरक्षा ही मिले उचित नहीं है।

श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा हटाई गई थी। श्री वीपी सिंह, श्री नरसिम्हा राव, श्री आईके गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुरक्षा को हटाकर जेड प्लस सिक्योरिटी से परिवर्तित किया गया, किंतु विपक्ष ने किसी तरह का शोर-शराबा नहीं किया।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून सभी के लिए बराबर होता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम परिवार का विरोध नहीं कर रहे हैं, परिवारवाद का विरोध करते हैं। परिवारवाद एक व्यवस्था है और इसका पुरविरोध करते रहेंगे। एक प्रश्न के जवाब में श्री शाह ने जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें लिखा था कि राजीव गांधी की हत्या करना इसलिए सरल हुआ, क्योंकि पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी।

श्रीमती प्रियंका वाड्रा के घर हाल में ही हुई घटना का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि उस दिन उनके घर आने वाली गाड़ी में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। उनका कहना था कि इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचना दी जा सकती थी।

संसद में पारित हुआ विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019

लोकसभा

बिल लाने का प्रमुख उद्देश्य सुरक्षा कवर को अधिक प्रभावी बनाना है

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए 27 नवंबर को कहा कि देश में ऐसा संदेश जा रहा है कि गांधी परिवार की सुरक्षा कम करने के लिए बिल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई नहीं गई है, बल्कि सीआरपीएफ की जेड प्लस (एएसएल) से बदली गई है और इसमें सुरक्षा बलों की संख्या पहले से अधिक हुई है जिसमें एंबुलेंस सुविधा भी शामिल है।

श्री शाह ने यह भी कहा कि इस परिवार ने अनेक बार बगैर एसपीजी को सूचना दिए बगैर यात्राएं की। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ सेंट्रल एजेंसी है और उसकी सुरक्षा पूरे देश में विद्यमान है और इस बिल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को पांच वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा कवर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक में पहले के बदलाव एक परिवार को ध्यान में रखकर हुए किंतु पहली बार प्रधानमंत्री को ध्यान में रखकर बदलाव किया जा रहा है।

श्री शाह का कहना था कि केवल गांधी परिवार ही नहीं देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। उनका कहना था कि सभी नागरिकों को सुरक्षा देने की मंशा भी है और धारणा भी किंतु सबको एसपीजी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

उनका कहना था कि पूर्णतया खतरे का आंकलन (थ्रेट असेसमेंट) के आधार पर सुरक्षा में बदलाव किए गए है। एक सदस्य के सवाल के जवाब में श्री शाह का कहना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में बड़े और कड़े मापदंड स्थापित किए हैं। श्री शाह का कहना था कि सिक्योरिटी कवर को स्टेटस सिंबल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि एसपीजी प्रोटेक्शन का मतलब देश के प्रधानमंत्री को कार्यालय, संचार, आरोग्य तथा सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देने से संख्या बढ़ती जाएगी जिससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। श्री शाह का कहना था कि इस बिल को लाने का प्रमुख उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवर को अधिक प्रभावी बनाना है। ■

संसद में दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 पारित

संसद में 3 दिसंबर को दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 पारित हो गया। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने राज्य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सार्थक उपयोग, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, प्रशासनिक व्यय कम करने, बेहतर ढंग से सेवाएं मुहैया कराने और योजनाओं की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों का बेहतर कैडर प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा।

श्री रेड्डी ने कहा कि प्रशासन एवं सेवा शर्तों और आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह समूह III और IV के कर्मचारियों की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विलय से प्रशासन में सहूलियत होगी, त्वरित विकास होगा और केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावकारी कार्यान्वयन हो पाएगा। श्री रेड्डी ने कहा कि इस नये केन्द्र शासित प्रदेश का नाम 'दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव' होगा और यह बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शासित होगा।

संशोधन करने के औचित्य के बारे में जानकारी देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि फिलहाल दो सचिवालय एवं समानांतर विभाग हैं, जो प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करते हैं। प्रशासक, सचिवालय और कुछ विशेष विभागों के प्रमुख वैकल्पिक दिवसों पर दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों में काम करते हैं, जिससे लोगों तक उनकी उपलब्धता और अधीनस्थ कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी प्रभावित होती है।

उन्होंने कहा कि दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के अधीनस्थ कर्मचारी अलग-अलग हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न विभागों को दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग ढंग से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जिससे कामकाज में दोहराव की स्थिति पैदा होती है।

श्री रेड्डी ने कहा कि दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों में दो भिन्न संवैधानिक एवं प्रशासनिक निकाय रहने से कामकाज में दोहराव एवं अक्षमता की स्थिति पैदा होती है और अपव्यय होता है। इसके अलावा, इस वजह से सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है। यही नहीं, कर्मचारियों के कैडर प्रबंधन और करियर में प्रगति के मार्ग में विभिन्न चुनौतियां हैं।

उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत अधिक अधिकारियों की उपलब्धता के साथ-साथ ज्यादा बुनियादी ढांचागत सुविधाएं मिलने से सरकार की प्रमुख योजनाओं का बेहतर ढंग से कार्यान्वयन करने में मदद मिलेगी। ■

और मजबूत हुआ भारत-जापान के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग

रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री श्री मोतेगी तोशीमित्सु और जापान के रक्षामंत्री श्री कोनो तारो के साथ 30 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में प्रथम भारत-जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।

मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि यह संवाद आपसी सुरक्षा और रक्षा सहयोग की सामरिक गहराई को और ज्यादा व्यापक बनाएगा। उभरती सुरक्षा चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मंत्रियों ने सुरक्षा सहयोग पर आधारित 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने से संबंधित 2009 की कार्य योजना के आधार पर द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस बात को स्मरण करते हुए कि दोनों देश मुक्त, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के प्रति समान दृष्टि रखते हैं, जिसके अंतर्गत सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत सुनिश्चित किए गए हैं और सभी देशों को नौवहन और उस क्षेत्र से उड़ान भरने की स्वतंत्रता है, मंत्रियों ने इस बात पर बल दिया कि द्विपक्षीय सहयोग और ज्यादा मजबूती प्रदान करना दोनों देशों के परस्पर हित में है तथा इससे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

द्विपक्षीय सहयोग

मंत्रियों ने पिछले साल द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में प्रगति का स्वागत किया। मंत्रियों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पिछले साल से भारत और जापान ने अपने रक्षा बलों के तीनों अंगों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास प्रारंभ किए हैं।

मंत्रियों ने दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नियमित रूप से आयोजित करने और उन्हें व्यापक बनाने के निरंतर प्रयास जारी रखने पर समान रूप से बल दिया। इस संदर्भ में मंत्रियों ने हाल ही में संपन्न द्वितीय 'धर्म गार्जियन-2019' और द्वितीय 'शिन्यू मैत्री-2019' का स्वागत किया। मंत्रियों ने जापान में प्रथम भारत-जापान संयुक्त लड़ाकू विमान अभ्यास के लिए समन्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति प्रकट की।

मंत्रियों ने अक्तूबर, 2018 में ऐक्विज़िशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट (एसीएसए) प्रारंभ किए जाने की घोषणा के बाद से इससे संबंधित बातचीत में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया। मंत्रियों ने विचार-विमर्श के जल्द समाप्त होने की इच्छा व्यक्त की और उनका

मानना था कि यह समझौता दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ाने में योगदान देगा।

खुले, मुक्त, समावेशी और नियमों पर आधारित हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सामुद्रिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकार करते हुए मंत्रियों ने सामुद्रिक सुरक्षा और अन्य देशों के साथ सहयोग के माध्यम से सामुद्रिक क्षेत्र सजगता में क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने की मंशा व्यक्त की। इस संदर्भ में मंत्रियों ने दिसम्बर, 2018 में भारत द्वारा सूचना समेकन केन्द्र-हिन्द महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) की स्थापना का स्वागत किया।

भारतीय पक्ष ने आईएफसी-आईओआर में जापान द्वारा एक सम्पर्क अधिकारी भेजे जाने की मंशा व्यक्त की। मंत्रियों ने पिछले साल जापान की मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच हस्ताक्षरित व्यापक सहयोग के लिए समझौते के क्रियान्वयन के आधार पर सूचना का आदान-प्रदान प्रारंभ होने की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

मंत्रियों ने रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने की जरूरत पर बल दिया तथा रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी सहयोग (जेडब्ल्यूजी-डीईटीसी) से संबंधित 5वें कार्य समूह में रचनात्मक विचार-विमर्श की इच्छा व्यक्त की। इस संदर्भ में मंत्रियों ने अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल (यूजीवी)/रोबोटिक्स के क्षेत्र में सहयोगपूर्ण अनुसंधान में हुई प्रगति का स्वागत किया।

मंत्रियों ने दोनों देशों की रक्षा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थाओं के बीच मौजूदा आदान-प्रदान कार्यक्रम की सराहना की और आदान-प्रदान कार्यक्रमों को जारी रखने और उनमें विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की।

बहुपक्षीय सहयोग

नवंबर, 2018 और जून, 2019 में हुई जापान-भारत-अमरीका शिखर बैठकों को याद करते हुए मंत्रियों ने अमरीका के साथ त्रिपक्षीय सहयोग को स्वीकार किया। मंत्रियों ने जापान के तट के समीप सितम्बर-अक्तूबर, 2019 में आयोजित 'मालाबार-2019', जापान में जुलाई, 2019 में आयोजित माइन-काउंटर मेजर एक्सरसाइज (एमआईएनईएक्स) तथा दिसम्बर, 2018 में आयोजित 'कोप इंडिया-2018', जिसमें जापान ने पर्यवेक्षक के तौर पर भाग लिया, में दर्शाये गए त्रिपक्षीय सहयोग पर संतोष प्रकट किया।

क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले

मंत्रियों के बीच विशेषकर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति सहित आपसी हित के क्षेत्रीय मामलों पर बेबाक और सार्थक विचार-विमर्श हुआ।

मंत्रियों ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में आसियान की केन्द्रीयता और एकता के महत्व की पुष्टि की। मंत्रियों ने थाइलैंड में जून, 2019 में आसियान के 34वें शिखर सम्मेलन के दौरान हिन्द-प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण (एओआईपी) को अंगीकार किए जाने का स्वागत किया।

मंत्रियों ने अपने साझा उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आसियान के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। मंत्रियों ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) जैसे आसियान के नेतृत्व वाले फ्रेमवर्क के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

जापानी पक्ष ने हाल ही में संपन्न 14वें ईएएस के दौरान सुरक्षित, संरक्षित, स्थिर, समृद्ध और टिकाऊ सामुद्रिक क्षेत्र का सृजन करने के लिए भारत द्वारा की गई 'हिन्द-प्रशांत महासागर पहल' की सराहना की और इस पहल के आधार पर ठोस सहयोग के बारे में विचार-विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की।

मंत्रियों ने मुक्त एवं खुले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए हाल की 'हिन्द-प्रशांत महासागर पहल' और एओआईपी सहित भारत और जापान की पहलों तथा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को समावेशी और क्षेत्र के सभी देशों के लिए खुला रखने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर संतोष प्रकट किया।

मंत्रियों ने उत्तर कोरिया द्वारा व्यापक संहार की क्षमता वाले सभी हथियारों और समस्त रेंज वाली बेलिस्टिक मिसाइलों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इससे संबंधित प्रस्तावों (यूएनएससीआर) के अनुरूप प्रमाणन योग्य एवं अपरिवर्तनीय ढंग से नष्ट करने के महत्व की पुष्टि की और यूएनएससीआर के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

मंत्रियों ने दक्षिण चीन सागर में हाल की घटनाओं के बारे में 14वें ईएएस के अध्यक्ष के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया। इस संदर्भ में मंत्रियों ने नौवहन और क्षेत्र से उड़ान भरने की स्वतंत्रता, अबाधित वैध व्यापार तथा संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) सहित कानूनी और सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों के अनुरूप कानूनी एवं राजनयिक प्रक्रियाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व की पुष्टि की।

मंत्रियों ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे की कड़े शब्दों में निंदा की और स्वीकार किया कि यह क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मंत्रियों ने सभी देशों से आह्वान किया कि वे आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाहों और बुनियादी ढांचे का सफाया करने, आतंकवादियों के नेटवर्क को बाधित करने तथा उन्हें वित्तीय सहायता देने वाले माध्यमों को समाप्त करने तथा सीमा पार आतंकवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने का संकल्प लें।

मंत्रियों ने इस बात की जरूरत पर बल दिया कि सभी देश यह सुनिश्चित करें कि उनकी धरती का इस्तेमाल अन्य देशों पर किसी भी तरह का हमला करने में नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में पाकिस्तान से गतिविधियां चलाने वाले आतंकवादियों के नेटवर्कों से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे का भी संज्ञान दिया।

मंत्रियों ने इस बात की जरूरत पर बल दिया कि सभी देश यह सुनिश्चित करें कि उनकी धरती का इस्तेमाल अन्य देशों पर किसी भी तरह का हमला करने में नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में पाकिस्तान से गतिविधियां चलाने वाले आतंकवादियों के नेटवर्कों से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे का भी संज्ञान दिया और इस संदर्भ में कड़ी और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने का आह्वान किया तथा एफएटीएफ सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह पालन करने का आह्वान किया। मंत्रियों ने सूचना और खुफिया जानकारी को साझा करने सहित आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से निपटने में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की जरूरत पर बल दिया।

मंत्रियों ने इस 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक की सफलता के मद्देनजर विचारों के निरंतर आदान-प्रदान के महत्व को मान्यता प्रदान की और अगली 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक टोक्यो में आयोजित करने का निर्णय लिया। ■

श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर का ऋण देगा भारत

श्रीलंका के नए राष्ट्रपति श्री गोटबाया राजपक्षे ने अपनी पहली आधिकारिक विदेशी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में 29 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में आतंकवाद से लेकर व्यापार समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही, भारत ने श्रीलंका को विकास परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा के अलावा आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए पांच करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की।

साझा प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत हर रूप में आतंकवाद का विरोध करता है और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, इस लड़ाई में भारत श्रीलंका का साथ देता रहेगा। दोनों देशों की साझा प्रेस वार्ता में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की जितनी भी नाव/बोट अभी श्रीलंका के कस्टडी में हैं अब श्रीलंका उन सभी को छोड़ देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना और पद संभालने के दो हफ्ते के भीतर भारत में हमें उनका सम्मान करने का मौका दिया। यह भारत और श्रीलंका के मित्रतापूर्ण संबंधों की मजबूती और गतिशीलता का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि यह इस बात का भी संकेत है कि दोनों देश इन संबंधों को कितना महत्व देते हैं। दोनों देशों की प्रगति और हमारे इस पूरे साझा क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए हम राष्ट्रपति राजपक्षे के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको प्राप्त जनादेश एक संगठित, मजबूत और समृद्ध श्रीलंका के लिए श्रीलंका के लोगों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है। इस संबंध में भारत की शुभेच्छा और सहयोग हमेशा श्रीलंका के साथ है। एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के हित में है, बल्कि संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र के भी हित में है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत श्रीलंका का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी और एक भरोसेमंद मित्र है। दोनों देशों के नज़दीकी संबंधों का मज़बूत आधार हमारे ऐतिहासिक, सजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी सरकार की "पड़ोसी प्रथम" नीति और सागर डॉक्ट्रिन के अनुरूप हम श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे दोनों देशों की सुरक्षा और विकास अविभाज्य हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम एक-दूसरे की सुरक्षा और संवेदनशीलताओं के प्रति सचेत रहें। श्री मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रपतिजी और मेरे बीच द्विपक्षीय संबंधों तथा परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बहुत अच्छी और लाभप्रद चर्चा हुई। हमने निर्णय लिया है कि दोनों देशों के बीच बहुमुखी साझेदारी और सहयोग को हम मिलकर और मज़बूत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने राष्ट्रपतिजी को श्रीलंका के साथ विकास साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है। हमेशा की तरह यह सहयोग

श्रीलंका के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुसार होगा। 400 मिलियन डॉलर के एक नए ऋण से श्रीलंका में अवसंरचना और विकास को बल मिलेगा।

श्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। साथ ही, यह ऋण दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभ के परियोजना सहयोग को भी गति देगा। हमें खुशी है कि इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में आंतरिक विस्थापितों के लिए 46,000 घर बन चुके हैं। अप-कंट्री रीजन में भारतीय मूल के तमिलों के लिए 14,000 घरों के निर्माण में अच्छी प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम श्रीलंका में सोलर प्रोजेक्टस के लिए पहले घोषित 100 मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन का जल्दी उपयोग में लाने पर सहमत हुए हैं। भारत द्वारा श्रीलंका में शिक्षा और अवसंरचना में अनुदान के आधार पर जारी 20 सामुदायिक विकास परियोजनाएं और अन्य जन केंद्रित परियोजनाओं पर भी राष्ट्रपतिजी और मेरे बीच अच्छी चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सदैव ही हर रूप में आतंकवाद का विरोध किया है और सीमा-पार आतंकवाद सहित अन्य प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपेक्षा भी की है। इस साल ईस्टर के अवसर पर श्रीलंका में आतंकियों ने पूरी मानवजाति की विविधता और सहजीवन की मूल्यवान विरासत पर नृशंस हमले किए। आतंकी एवं चरमपंथी ताकतों के विरुद्ध श्रीलंका की लड़ाई में भारत का अटल समर्थन व्यक्त करने मैं भारत में चुनावों के तुरंत बाद श्रीलंका गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसी सुरक्षा के लिए और आतंकवाद के विरुद्ध आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर मैंने राष्ट्रपति राजपक्षे के साथ विस्तार से चर्चा की है। प्रमुख भारतीय संस्थानों में श्रीलंका के पुलिस अधिकारी आतंकरोधी प्रशिक्षण का लाभ पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए श्रीलंका को 50 मिलियन डॉलर की एक विशेष ऋण की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि मछुवारों की आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी चर्चा की। ■

'बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर'

भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में बाबासाहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि व महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि व संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

बाबासाहेब डॉ. भीम रॉव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर केन्द्रीय कार्यालय में पुष्पांजलि व "भारतीय संविधान और सामाजिक चेतना'' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री थावरचन्द गेहलोत, केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार व कार्यक्रम के अतिथि श्री सोमप्रकाश, केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री विनोद सोनकर, सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा, भाजपा ने की।

संगोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बाबासाहेब जी के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी का विराट व बहुआयामी व्यक्तित्व है। बाबासाहेब पत्रकार, लेखक, दार्शनिक, विधिज्ञाता, विचारक, सामाजिक आन्दोलनकारी, आधुनिक भारत के निर्माता थे। बाबासाहेब विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए स्वतन्त्र भारत को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान तैयार किया। बाबासाहेब के द्वारा तैयार किया गया संविधान भारत का मार्ग प्रशस्त करता है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री थावरचन्द गेहलोत ने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार ही बाबासाहेब अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा कर रही है। गत 50 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने बाबासाहेब को अपमानित व उपेक्षित करने का कार्य किया। मोदी सरकार ने ही बाबासाहेब के प्रत्येक प्रतीक चिन्ह जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, शिक्षा भूमि व महापरिनिर्वाण स्थल 26 अलीपुर रोड सभी को भव्य स्मारक बनाने का कार्य किया। बाबासाहेब के स्मृति में डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र जनपथ दिल्ली, 21 विश्वविद्यालयों में अम्बेडकर चेयर की स्थापना की, इस प्रकार बाबासाहेब को सम्मानित करने का लगातार प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री विनोद सोनकर ने की व स्वागत में श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री थावर चन्द गहलोत व श्री सोमप्रकाश को संविधान की प्रति भेंट की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा 26 नवम्बर संविधान दिवस से 6 दिसम्बर परिनिर्वाण दिवस तक इस पखवाड़े में देश भर के जिलास्तर पर संविधान दिवस व महा परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम आयोजित किये गये। देश के 26 प्रदेशों में जिलास्तर पर संविधान दिवस व परिनिर्वाण दिवस के सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित हुये। मंच का संचालन प्रो. राजकुमार फलवारिया ने किया। ■

राष्ट्र ने डॉ. बीआर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 6 दिसंबर को संसद भवन लॉन में आयोजित समारोह में राष्ट्र की ओर से भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. बी आर अम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबासाहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

डॉ. अम्बेडकर को उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने भी पुष्पांजलि अपर्ति की। महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबासाहेब को पुष्पांजलि अर्पित करने वाले नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, केन्द्रीय सामाजिक तथा न्याय अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलौत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री राम दास अठावले, श्री कृष्ण पाल गुर्जर तथा अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल थे। समारोह का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत स्वशासी संगठन अम्बेडकर फाउंडेशन ने किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा "सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले पूज्य बाबासाहेब को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि-कोटि नमन। उन्होंने संविधान के रूप में देश को अद्वितीय सौगात दी, जो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। कृतज्ञ राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा।"

भाजपा को राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान सुशासन, पारदर्शी और स्थिर सरकार देने का लाभ मिलेगा: ओपी माथुर

झारखंड विधानसभा चुनाव एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड चुनाव प्रभारी श्री ओम माथुर से नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर कमल संदेश के विपुल शर्मा ने बातचीत की। श्री माथुर का कहना है कि झारखंड में भाजपा की ईमानदार और पारदर्शी सरकार के चलते पार्टी को विशाल जनसमर्थन मिला रहा है। वहीं, उनका मानना है कि मोदी सरकार की योजनाओं ने बड़े स्तर पर लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर देश मजबूत हुआ है और राज्य में नक्सल समस्या पर भी लगाम लगा है, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। प्रस्तुत है इस बातचीत के मुख्यांश :

झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर आपका क्या आकलन है?

झारखंड राज्य कुल 5 परिमंडलों में विभाजित है और इन पांचों परिमंडलों की सांस्कृतिक भिन्नता को साफ देखा जा सकता। हर परिमंडल सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से अलग है। तो इस बात को ध्यान में रखकर हमें अपनी चुनावी रणनीति का निर्माण करना पड़ा। अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, उसमें 13 सीटों के लिए मतदान हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर इस चरण के चुनावों में सफल होने जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव पूर्ण होने के बाद जो आंकड़ें सामने आ रहे है उसमें लोकसभा चुनावों के दौरान हुए मतदान प्रतिशत में 1.44 प्रतिशत वृद्धि देखी जा रही है। यह सीधा संकेत है कि हमने बूथ स्तर पर जो कार्य किया, उसकों जनता का सीधा समर्थन मिल रहा है।

दूसरे चरण का चुनाव कोलहान परिमंडल में होना है। पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी को सबसे कम सीटें इसी परिमंडल में मिली थी। उसको ध्यान में रखकर हमनें कड़ी मेहनत की है और हमकों पूर्ण विश्वास है कि पार्टी इस बार यहां पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसके अतिरिक्त हमने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की रैलियों का आयोजन राज्य की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए किया है। अब तक राज्य में हमारी चार रैलियां हो चुकी हैं और इन रैलियों के दौरान मिलने वाला जनसमर्थन हमारी सोच से भी बढ़कर रहा है।

आपने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने के लिए कौन से कदम उठाए?

हमने झारखंड चुनावों को लेकर अपनी रणनीति पर बहुत पहले से ही कार्य करना आरंभ कर दिया था। जैसाकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की योजना बनायी थी, उसी को आगे बढ़ते हुए हमने राज्य के लगभग 29400 बूथ पर बूथ प्रमुख और टीम का गठन किया। इसमें संबंधित इलाके की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। दूसरी बात, इस बार राज्य में पन्ना प्रमुख स्तर पर भी काफी बेहतर काम हुआ है और सभी विधानसभाओं की कोर टीम बनी है। इन चुनाव की सारी व्यूह रचना को संगठन टीम के अनुरूप ही किया गया है। हमनें चुनावी रणनीति को दो हिस्सों में बांटा था, जिसमें एक इसका तकनीकी पक्ष था और दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष था। तकनीकी पक्ष का दायित्व विशुद्ध रूप से संगठन के जिम्मे होता है और इसकी पहुंच सीधे मतदाता तक होती है, जिसमें सामाजिक समीकरणों के आधार पर टिकटों का बंटवारा, सामाजिक समीकरणों के आधार पर लोगों के प्रवास सुनिश्चित करना और हर लोकसभा एवं विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति इसकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल है और हम निरंतर अपने काम की समीक्षा करते रहे।

भाजपा राज्य में एक स्थिर सरकार देने में कामयाब रही है। क्या इसका चुनावी लाभ पार्टी को आगामी चुनावों में मिलेगा?

झारखंड को अस्तित्व में आए 19 साल हुए और इस दौरान राज्य राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। यह पहली बार है कि भाजपा

के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार राज्य की सत्ता में आयी जिसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। जनता पर इस बात का भी गहरा प्रभाव पड़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बात का लाभ चुनावों में भाजपा को निश्चित तौर पर मिलेगा।

केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना असर आप इन चुनावों में देख रहे हैं?

मेरी नजर में झारखंड इस मामले में पिछले पांच सालों में बेहद सौभाग्यशाली रहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा सरकार रहीं और इस डबल इंजन वाली सरकार का लाभ राज्य की जनता को पूर्ण रूप से मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांव, गरीब और किसानों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई, उनका लाभ झारखंड की जनता को भी मिला। हमने लगभग सभी विधानसभाओं में इन योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया और ऐसा देखा गया कि इन योजनाओं का लाभ उठाने वालों में लगभग 90 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं है, जो बेहद हर्ष का विषय है। उज्ज्वला योजना, राज्य सरकार द्वारा फ्री सलेंडर रीफिल योजना, आवास योजना, किसान निधि और जनधन, सड़क निर्माण जैसी योजनाओं का लाभ भी प्रदेश की जनता तक पहुंच रहा है।

पिछले पांच सालों में भाजपा विकासपरक सरकार देने में कामयाब रही है, राज्य सरकार की उपलिब्धयों को आप कैसे देखते हैं?

पिछले पांच सालों के दौरान भाजपा सरकार नक्सल समस्या पर बहुत हद तक लगाम लगाने में सफल रही है। देखा जाए तो इस दौरान नक्सलवाद की कुल चार या पांच बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो नक्सलवाद पर लगाम का आम मतदाता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार 38 लाख किसानों को सालाना 31 हजार रुपये की सहायता राशि दे रही है, 28 लाख किसानों को निःशुल्क मोबाइल मिले है, महिलाओं के नाम पर 50 लाख तक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मात्र एक रुपए में की जा रही है, राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति विकास निगम का गठन किया गया, आदिवासी गांवों में आदिवासी विकास समिति के माध्यम से 5 लाख तक के कार्य करने का अधिकार इन समितियों को दिया गया। यह कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य में विकास को एक नया आयाम दे रही हैं और इनका लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है। ■

तीनों सेनाओं के लिए 22,800 करोड़ रुपये के पूंजीगत सामान की खरीद को मंजूरी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक 28 नवंबर को हुई, जिसमें तीनों सेनाओं के लिए 22,800 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य के पूंजीगत सामान की खरीद को मंजूरी दी गई। 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए डीएसी ने असॉल्ट राइफलों हेतु 'थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स' के स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण के लिए मंजूरी दी। 'थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स' का विनिर्माण भारत के निजी उद्योग द्वारा किया जाएगा और इनका उपयोग अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों द्वारा किया जाएगा।

'थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स' से सैनिकों को अंधेरे के साथ-साथ हर तरह के मौसम में लम्बी दूरी से सटीक निशाना लगाने में मदद मिलेगी, जिससे रात्रि में भी बड़ी तत्परता के साथ जंग करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी।

सफल स्वदेशी 'एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (एईडब्ल्यूएंडसी)' कार्यक्रम के बाद डीएसी ने अतिरिक्त एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एडब्ल्यूएसीएस) इंडिया एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकार्यता को दोबारा सत्यापित किया। इन विमानों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा मिशन प्रणालियों और उप-प्रणालियों की स्वदेश में ही डिजाइनिंग की जाएगी और फिर इनका विकास किया जाएगा तथा बाद में मुख्य प्लेटफॉर्म पर इन्हें एकीकृत किया जाएगा।

ये प्लेटफॉर्म विमान पर ही कमांड एवं कंट्रोल तथा 'पूर्व चेतावनी' सुलभ कराएंगे, जिससे भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को हवाई क्षेत्र में कम से कम समय में प्रभावकारी वर्चस्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इन प्रणालियों को शामिल करने से हमारे देश की सीमाओं पर कवरेज बढ़ जाएगी और इससे भारतीय वायु सेना की हवाई रक्षा तथा आक्रामक क्षमता दोनों को ही काफी हद तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।

डीएसी ने नौसेना के लिए मध्यम दूरी वाले 'पनडुब्बी-रोधी युद्ध पी8 I' विमान की खरीद को भी मंजूरी दे दी। इन विमानों से समुद्री तटों की निगरानी, पनडुब्बी-रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू) और एंटी-सरफेस वेसल (एएसवी) से हमले करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी।

डीएसी ने भारतीय तटरक्षक के लिए 'ट्विन इंजन हैवी हेलिकॉप्टर (टीईएचएच)' की खरीद को भी स्वीकृति दे दी। इन विमानों से तटरक्षक को समुद्र में आतंकवाद की रोकथाम करने और समुद्री मार्गों के जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के साथ-साथ तलाशी एवं बचाव अभियान चलाने के मिशन शुरू करने में मदद मिलेगी। ■

जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की

भारत-जापान विदेश एवं रक्षा मंत्री संवाद (2+2) के उद्घाटन बैठक में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आए जापान के विदेश मंत्री श्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री श्री तारो कोनो ने 30 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने आगन्तुक मंत्रियों का स्वागत किया और अक्टूबर, 2018 में जापान में आयोजित 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान स्वयं और जापान के प्रधानमंत्री श्री अबे द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में दोनों पक्षों के सक्षम होने पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

श्री मोदी ने बताया कि यह बैठक भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय रणनीति, सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगी। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों, क्षेत्र और पूरी दुनिया के लाभ के लिए भारत-जापान संबंधों के सर्वांगीण विकास के महत्व पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच नियमित तौर पर उच्च स्तरीय विनिमय रिश्ते की गहराई और ताकत का प्रमाण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे और प्रधानमंत्री अबे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने बताया कि वे अगले महीने भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री अबे का भारत में स्वागत करने को उत्सुक हैं।

श्री मोदी ने कहा कि जापान के साथ भारत का संबंध भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारी दृष्टि का एक प्रमुख घटक है और इसके साथ ही भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आधारशिला भी है। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी,
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह
और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविन्द जगन्नाथ से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

संसद भवन परिसर में डॉ. भीमराव अम्बेडर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में नवोन्मेष नीति पर भारत–स्वीडन उच्चस्तरीय नीति वार्ता में भाग लेते स्वीडन के राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

बोकारो (झारखंड) में एक विशाल रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20